RNI No. : DELHI/2014/56101

वर्ष : 13 अंक : 180

नई दिल्ली, मंगलवार

29 जून 2026

मूल्य : 03 रुपए पृष्ठ 08

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक
वेब वार्ता

हर संघर्ष में आपके साथ

दिल्ली एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री व अन्य ने पी.वी. नरसिम्हा राव को जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई नेताओं ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पी.वी. नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिरला ने एक्स पर कहा, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न दिवंगत पी.वी. नरसिम्हा राव की जयंती पर सविनय नमन।देश की प्रगति के लिए नीति निर्माता के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने देश के इतिहास के एक अहम दौर में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वे एक विद्वान भी थे और उन्हें भारत की विविध संस्कृति का गहरा ज्ञान और समझ थी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक दूरदर्शी नेता और राजनेता के तौर पर पी. वी. नरसिम्हा राव ने भारत की आर्थिक यात्रा में एक अहम भूमिका निभाई। देश के लिए उनके योगदान और उनके जीवन को हमेशा याद किया जाएगा।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा शुरू किए गए क्रांतिकारी आर्थिक उदारीकरण ने विकास की गति बढ़ाई, मध्यम वर्ग के लिए अवसर बढ़ाए और देश को दीर्घकालिक विकास की राह पर अग्रसर किया। उनके कार्यकाल में भारत के परमाणु कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हुई और दूरदर्शी कूटनीतिक पहलें की गईं, जिनमें ऐतिहासिक 'लुक ईस्ट' नीति भी शामिल है। भारत की प्रगति और राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

केंद्रीय कोयला एवं खानमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य के गौरवशाली सपूत और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पी.वी. नरसिम्हा राव गारू को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। एक दूरदर्शी, विद्वान और बेहतरीन प्रशासक के तौर पर, देश की प्रगति और हैदराबाद मुक्ति संग्राम में उनका योगदान उल्लेखनीय है।

प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। पर्यावरण कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने रविवार को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने यह जानकारी दी। श्री दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा, "सोनम वांगचुक ने विद्यार्थियों के लिए इंसाफ लेने तथा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है।"

इससे पहले श्री वांगचुक राजघाट गये थे। यहां सीजेपी के संस्थापक श्री दिपके और सौरव दास उनके साथ मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि श्री दिपके ने रविवार सुबह 11 बजे लोगों से जंतर-मंतर आने की अपील की थी। उन्होंने एक पोस्ट में यह भी दावा किया था कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई किसान नेताओं को नज़रबंद किया जा रहा है ताकि वे जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल न हो सकें। यह जानकारी दी।

भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, आतंकवाद को पनाह देने वाले दूसरों पर ना उठाएं उंगली

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। भारत ने कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि आतंकवाद को पालने वाले देश को दूसरे पर अंगुली उठाने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में रविवार को कहा, "हमने कराची में हाल ही में हुई घटना के संबंध में भारत के विरुद्ध निराधार आरोप लगाने वाली पाकिस्तान की रिपोर्टें देखी हैं।

हम इन आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। दूसरों पर अंगुली उठाने के बजाय, पाकिस्तान को अपने भीतर झाँकना चाहिए, अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकवादी ढाँचे के विरुद्ध विश्वसनीय कार्रवाई करनी चाहिए तथा राज्य की नीति के एक साधन के रूप में आतंकवाद पर निर्भर रहने की अपनी प्रवृत्ति का परित्याग करना चाहिए।" उल्लेखनीय है कि इस हमले में पाकिस्तान के चार रेंजर्स के मारे जाने की खबर है।

कश्मीर दौरे पर सीईसी ज्ञानेश कुमार, बीएलओ से करेंगे संवाद

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) आज से तीन दिवसीय कश्मीर दौरे पर हैं। इस क्रम में वह रविवार दोपहर राजधानी श्रीनगर पहुंचे।

इस दौरे के दौरान, सीईसी जम्मू-कश्मीर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इन कार्यक्रमों का मकसद मतदाताओं और बडगाम जिले में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से जुड़ना, साथ ही चुनाव से जुड़े अन्य लोगों और जमीनी स्तर पर काम करने वाली चुनाव मशीनरी से मिलना है। वह जमीनी स्तर पर चल रही चुनाव से जुड़ी विभिन्न पहलों की समीक्षा भी करेंगे।

शेख-उल-आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर सीईसी का स्वागत जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव वर्मा, बडगाम के डिप्टी कमिश्नर अथर आमिर खान और चुनाव विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय प्रतिभा नौशीन फातिमा खान ने लहराया हिंद का परचम

एथेंस में काउंसलिंग साइकोलॉजी में सर्वोच्च सम्मान से बढ़ाया देश का मान

➲ नई दिल्ली/ एथेंस, (वेब वार्ता)।

नई दिल्ली की छात्रा नौशीन ने ग्रीस के अमेरिकन कॉलेज ऑफ ग्रीस, एथेंस से काउंसलिंग साइकोलॉजी कार्यक्रम में सर्वोच्च क्यूम्युलेटिव ग्रेड इंडेक्स प्राप्त कर भारत का गौरव बढ़ाया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 26 जून को आयोजित दीक्षांत समारोह में उन्हें प्रतिष्ठित ऑनर रोल सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान केवल उस छात्र या छात्रा को दिया जाता है, जिसने अपने पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया हो।

ग्रीस के अमेरिकन कॉलेज ऑफ ग्रीस, एथेंस में अध्ययनरत भारतीय छात्रा नौशीन ने काउंसलिंग साइकोलॉजी कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च क्यूम्युलेटिव ग्रेड इंडेक्स प्राप्त किया। इसके लिए कॉलेज ने उन्हें अपने प्रतिष्ठित Honor Roll सम्मान से नवाजा।

कॉलेज प्रशासन ने इस उपलब्धि पर नौशीन के साथ-साथ उनके माता-पिता और शिक्षकों को भी बधाई देते हुए इसे संस्थान के लिए गर्व का विषय बताया।

ऑनर रोल सम्मान संस्थान द्वारा उस छात्र या छात्रा को प्रदान किया जाता है, जिसने अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक क्यूम्युलेटिव ग्रेड इंडेक्स क्यूम्युलेटिव ग्रेड इंडेक्स प्राप्त किया हो।

नौशीन ने परिवार और देश को दिया उपलब्धि का श्रेय

सम्मान प्राप्त करने के बाद नौशीन ने कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि उनके परिवार और भारत के लिए भी गर्व का विषय है। उन्होंने विदेश में शिक्षा के दौरान मिली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी यह उपलब्धि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखने वाले भारतीय युवाओं को प्रेरित करेगी।

मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते काउंसलिंग साइकोलॉजी और संबंधित क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर करियर की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे समय में नौशीन की यह उपलब्धि भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण मानी जा रही है।

विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में सर्वोच्च शैक्षणिक प्रदर्शन कर ऑनर रोल प्राप्त करना न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह भारतीय छात्रों की वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक उत्कृष्टता का भी प्रमाण है।

26 जून को एथेंस में आयोजित दीक्षांत समारोह में नौशीन ने पारंपरिक शैक्षणिक परिधान में मंच पर पहुंचकर सम्मान ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संस्थान के साथ-साथ भारत का भी गौरव बढ़ाया।

- नई दिल्ली की छात्रा नौशीन को ग्रीस में मिला प्रतिष्ठित सम्मान।
- काउंसलिंग साइकोलॉजी कार्यक्रम में सर्वोच्च क्यूम्युलेटिव ग्रेड इंडेक्स हासिल किया।
- 26 जून को दीक्षांत समारोह में ऑनर रोल से सम्मानित किया गया।
- यह सम्मान पाठ्यक्रम में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को दिया जाता है।
- कॉलेज प्रशासन ने छात्रा, परिवार और शिक्षकों को बधाई दी।
- भारत के लिए गर्व का क्षण।

उनकी यह उपलब्धि देशभर के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है और यह संदेश देती है कि समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर वैश्विक स्तर पर भी पहचान बनाई जा सकती है।

समुद्र से आसमान तक भारत बन रहा है आत्मनिर्भर : मोदी

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत समुद्र से लेकर आसमान तक रक्षा क्षेत्र में तेजी से अधिक सुरक्षित तथा आत्मनिर्भर बन रहा है और स्वदेशी तकनीक तथा विनिर्माण के दम पर देश नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

श्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' के 135 वीं कड़ी में कहा कि 2026 का आधा हिस्सा बीतने को है और इन छह महीनों में देश ने सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हर देशवासी को गर्व है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को शामिल किया गया। इन युद्धपोतों का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह स्वदेशी है।

श्री मोदी ने कहा कि जून में ही विमानन क्षेत्र में भी बड़ी सफलता मिली है। 'मेक इन इंडिया' के तहत निर्मित सी-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एयरोस्पेस क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और सशक्त होगा।

उन्होंने कहा कि इसी महीने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी लंबी दूरी की भूमि-आक्रमण क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों की साझेदारी से विकसित की गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्पष्ट है कि आज भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में 'नशा मुक्त भारत' सम्मेलन में भाग लिया

➲ बेंगलुरु, (वेब वार्ता)।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस और 'नशा मुक्त भारत' सम्मेलन में भाग लिया।

यहां आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि यह शिक्षा प्राप्ति, उत्पादकता, सामाजिक एकजुटता और राष्ट्रीय विकास को भी प्रभावित करता है।

उन्होंने कहा कि मैं हमारे शैक्षणिक संस्थानों से आग्रह करता हूं कि वे एडिक्शन मेडिसिन, मानसिक स्वास्थ्य और समुदाय-आधारित उपायों पर शोध को और मजबूत करते रहें। 'नशा मुक्त भारत' का विन केवल नशीले पदार्थों का न होना नहीं है, बल्कि स्वस्थ विकल्पों का होना है। आइए, हम एक ऐसा भविष्य बनाने का संकल्प लें जहां हर युवा को आगे बढ़ने और फलने-फूलने का अवसर

मिले। इस दौरान उप-राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने 'राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान' के तहत शिशुओं को पोलियो वैक्सीन की बूंदें भी पिलाईं।

वहीं, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर कर्नाटक में बिकने वाले किसी भी तरह के पान मसाला और गुटखा में थोड़ी भी मात्रा में नशीले पदार्थ पाए गए, तो उनकी बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि पान मसाला, गुटखा, सुपारी से बने उत्पादों और ऐसी ही दूसरी चीजों में नशीले पदार्थ मिलाकर बाजार में बेचे जा रहे हैं। अगर यह सच है और इसे तुरंत नहीं रोका गया, तो कर्नाटक में सभी तरह के पान मसाला और गुटखा उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य नशा-मुक्त कर्नाटक बनाना है। इसीलिए हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 'नशा मुक्त भारत' अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी इस मिशन के एंबेसडर हैं। नशीली दवाओं की लत को रोकना एक बड़ी चुनौती है, और हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि युवा पीढ़ी नशे की लत के जाल में न फंसे। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। लोगों की जान बचाने जैसे नेक काम को चुनने के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं।

इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जस्टिस (रिटायर्ड) एस. अब्दुल नजीर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

'एनीमिया मुक्त भारत अभियान' के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस होगी जारी

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में एनीमिया से निपटने की कोशिशों को तेज करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इस क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 29 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक के दौरान 'एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) अभियान – ऑपरेशनल गाइडलाइंस' जारी करेंगे।

यह लॉन्च एनीमिया के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक अहम पड़ाव होगा, क्योंकि यह कार्यक्रम 'एनीमिया मुक्त भारत' से 'एनीमिया मुक्त भारत अभियान' में बदल रहा है। यह बदलाव इसे और ज्यादा व्यापक, लोगों पर केंद्रित और टेक्नोलॉजी-आधारित पहल बनाता है। यह लॉन्च कार्यक्रम के इस बदलाव को औपचारिक रूप भी देगा और इसके एक ऐसे समग्र दृष्टिकोण में विकसित होने को दिखाएगा जो सिर्फ आयरन सप्लीमेंटेशन से आगे बढ़कर टेस्टिंग, इलाज, सही खान-पान, डिजिटल ट्रैकिंग और 'जन चेतना' के जरिए सामुदायिक भागीदारी को भी शामिल करता है।

ये गाइडलाइंस मौजूदा 6-6-6 रणनीति को 7-7-7 फ्रेवर्क में बदल देंगी, जिसमें सातवां लाभार्थी समूह, सातवां इंटरवेंशन और सातवां संस्थागत तंत्र शामिल होगा। जीवन की शुरुआती अवस्था से ही एनीमिया की समस्या से निपटने के महत्व को समझते हुए, कम वजन (एलबीडब्ल्यू) वाले बच्चों (0-6 महीने) को सातवें लाभार्थी समूह के तौर पर शामिल किया जाएगा।

'ईटिंग राइट' का तरीका, जो रोजाना विविध आहार लेने की आदत को बढ़ावा देगा, सातवें हस्तक्षेप के तौर पर शुरू किया जाएगा, जबकि डिजिटल ट्रैकिंग से मूल्यांकन फ्रेमवर्क सातवें संस्थागत तंत्र के तौर पर काम करेगा।

समुद्री सुरक्षा को मिली नई ताकत :

भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ स्वदेशी फास्ट पेट्रोल पोत आईसीजीएस अक्षय

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता को और मजबूत करते हुए अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल पोत आईसीजीएस अक्षय को अपने बेड़े में शामिल किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा में आयोजित समारोह में इस नए पीढ़ी के पोत का विधिवत कमीशन किया गया।

पोत को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की अतिरिक्त सचिव श्रीमती परमा सेन, आईएएंडएएस ने सेवा में शामिल किया। इस अवसर पर तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्र के कमांडर महानिरीक्षक भीष्म शर्मा, पीटीएम, टीएम, उप महानिदेशक (मानव

संसाधन विकास) महानिरीक्षक ज्योतिंद्र सिंह, टीएम, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

'अक्षय' का अर्थ है—अविनाशी। यह नाम भारतीय तटरक्षक बल की अटूट प्रतिबद्धता, साहस और समुद्री हितों की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। यह पोत सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने की दिशा में तटरक्षक बल की भूमिका को और प्रभावी बनाएगा।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित आईसीजीएस अक्षय आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के घरेलू रक्षा एवं समुद्री उद्योग तंत्र को मजबूती प्रदान करता है।

आईसीजीएस अक्षय समुद्री कानूनों के पालन, खोज एवं बचाव अभियान, तटीय सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण और संकट में फंसे नाविकों की सहायता जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाएगा।

कमांडेंट (जूनियर ग्रेड) दीपक चौबे के नेतृत्व में यह पोत और इसका चालक दल भारतीय तटरक्षक बेड़े का हिस्सा बन गया है। इसके शामिल होने से तटरक्षक बल के आधुनिकीकरण अभियान को नई गति मिलेगी और सुरक्षित एवं सशक्त समुद्री भारत के निर्माण में योगदान बढ़ेगा।

संपादकीय

संविधान बनाम मनुस्मृति : राष्ट्रवाद की आड़ में आरएसएस का दलित स्वाभिमान पर हमला

50 साल तिरंगे का विरोध, संविधान की जगह मनुस्मृति : आरएसएस के 'सांस्कृतिक' दावे की पोल खोलते तथ्य

भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के ताने-बाने में आज एक गंभीर वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारत का समतामूलक संविधान है, जो हर नागरिक को समानता, गरिमा और अभिव्यक्ति की आजादी देता है; तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसी संस्थाओं की वह कथित विचारधारा है, जिस पर समय-समय पर जातिवादी मानसिकता और संकीर्णता के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। यह विमर्श तब और तीखा हो जाता है जब राज्य की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत संवैधानिक पदों पर बैठे ज़िम्मेदार राजनेताओं द्वारा उठाए गए प्रशासनिक सवालों को हल करने के बजाय, उनकी पहचान को महज 'जाति' के चश्मे से देखा जाने लगता है।

समरसता का दावा और जातिवादी दृष्टिकोण का विरोधाभास

आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठन सार्वजनिक मंचों से 'सामाजिक समरसता' और 'हिंदू एकता' का पुरजोर दावा करते हैं। लेकिन जब कर्नाटक के गृहमंत्री प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए संगठन के पंजीकरण (Registration) से संबंधित सवाल पूछते हैं, तो विमर्श का रुख प्रशासनिक जवाबदेही से भटकाकर जातिगत पहचान पर केंद्रित कर दिया जाता है। आलोचकों और समाज के बड़े हिस्से का आरोप है कि संघ और उसके समर्थकों द्वारा एक राज्य के गृहमंत्री की प्रशासनिक योग्यता और संवैधानिक गरिमा को दरकिनार कर, उन्हें यह कहकर लांछित किया जाता है कि ₹तुम दलित हो, तुम आरएसएस से सवाल क्यों कर रहे हो?₹

इस तरह के बयानों से संघ की वही पुरातनपंथी सोच खुलकर उजागर होती है, जहां किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके ज्ञान, पद, राष्ट्र-सेवा या प्रशासनिक क्षमता से नहीं, बल्कि उसकी जन्म-आधारित जाति से होता है। गृहमंत्री के प्रति दिए गए ऐसे बयानों से आज देश का पूरा दलित समाज आक्रोशित है और खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। इसी दोहरेपन के कारण आज देश के गली-मोहल्लों से लेकर मुख्यधारा के विमर्शों में संघ की प्राथमिकताओं पर तीखे सवाल उठने लगे हैं। जनता के बीच यह चर्चा आम हो चली है कि क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत को मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाएं और सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए, और क्या एक गैर-पंजीकृत संगठन को देश की नीतियों में हस्तक्षेप की अनुमति होनी चाहिए?

ऐतिहासिक अंतर्विरोधः राष्ट्रध्वज, संविधान और वैधानिक स्थिति से परहेज

संघ के इतिहास और उसकी घोषित नीतियों को लेकर अक्सर निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर उसकी राष्ट्रवाद की परिभाषा को कटघरे में खड़ा किया जाता हैः

राष्ट्रध्वज (तिरंगे) के प्रति उपेक्षा का इतिहासः भारत की आजादी के समय संघ के आधिकारिक मुखपत्र ऑर्गनाइज़र (14 अगस्त 1947 के अंक) में तिरंगे को लेकर जो बातें लिखी गईं, वे ऐतिहासिक रूप से दर्ज हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया था कि ₹हिंदुस्तान में तीन रंगों का ध्वज कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा।₹ यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद एक लंबे समय (लगभग 52 वर्षों) तक नागपुर स्थित संघ मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, जिसे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति उनके पूर्ण समर्पण की कमी के रूप में देखा जाता है।

संविधान बनाम मनुस्मृति का वैचारिक द्वंद्वः बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को जब देश ने अपनाया, तब संघ के वैचारिक हलकों में मनुस्मृति के प्रति खुला झुकाव देखा गया। ऑर्गनाइज़र के नवंबर 1949 के अंकों में भारतीय संविधान की इस बात के लिए आलोचना की गई थी कि इसमें प्राचीन ग्रन्थों (मनु के नियमों) को स्थान नहीं दिया गया। दलित विचारकों का मानना है कि मनुस्मृति जैसी व्यवस्था का समर्थन करना अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक असमानता और जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना है, जो दलित स्वाभिमान पर सीधा हमला है।

वैधानिक जवाबदेही से दूरीः आरएसएस खुद को एक औपचारिक और पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित करने के बजाय 'व्यक्तियों का समूह' बताता है। इस पर अक्सर यह आरोप लगता है कि यह कानूनी ऑडिट, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही से बचने की एक सोची-समझी रणनीति है। विरोधाभास तब और गहरा जाता है जब देश के प्रधानमंत्री इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ (NGO) स्वीकार करते हैं या सरकारी स्तर पर इसके नाम से डाक टिकट जारी किए जाते हैं, लेकिन संगठन स्वयं को किसी ठोस वैधानिक और कानूनी ढांचे में बांधने से कतराता है।

दलित समाज की लामबंदी और प्रतिबंध की मांग

इस वैचारिक और सामाजिक दोहरेपन के खिलाफ आज देश का दलित समाज पूरी तरह एकजुट, लामबंद और जागरूक नजर आ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और रोजगार जैसे बुनियादी और मौलिक अधिकारों को जब छद्म राष्ट्रवाद या धार्मिक नारों के पीछे छुपाने की कोशिश की जाती है, तो समाज का पढ़ा-लिखा तबका इसे अपने अधिकारों और अस्तित्व पर आघात मानता है।

यही कारण है कि आज देश के कई हिस्सों में संगठन की पारदर्शिता को लेकर और उस पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांगें फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। लोग अब यह बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी संगठन को बिना वैधानिक पंजीकरण, बिना ऑडिट और बिना किसी कानूनी जवाबदेही के काम करने की असीमित छूट क्यों मिलनी चाहिए?

बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि ₹राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल न हो जाए।₹ यदि भारत को वास्तव में 'वसुधैव कुटुंबकम' (पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है) के सिद्धांत पर आगे बढ़ाना है, तो देश को किसी गुप्त एजेंडे, संगठन की तानाशाही या पुरातनपंथी संकीर्णता के आधार पर नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के 'राजधर्म' के आधार पर चलाना होगा। जब तक हर नागरिक को जातिगत पहचान से ऊपर उठकर संवैधानिक सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक समरसता की बात केवल एक राजनीतिक छलावा ही रहेगी। दलित समाज की यह बढ़ती लामबंदी देश में वास्तविक लोकतंत्र और समतामूलक समाज की स्थापना का शंखनाद है।

कपिल बर्मन

बादल है पर बूँद नहीं

बादल है पर बूँद नहीं, कैसी ऋतु की चाल।
प्यासे मन की देह पर, सूखा हर इक ताल॥
धरा तड़पती देखिए, फटते जाएँ खेत।
आशा के अंकुर सभी, माँग रहे हैं मेघ॥
आँखों में बरसात है, सूना नभ का भाल—
बादल है पर बूँद नहीं, कैसी ऋतु की चाल॥
वादों वाले मेघ हैं, देते केवल शोर।
बरसे एक बूँद भी नहीं, सूखे गाँव-छोर॥
झूठी बातें ओढ़कर, चलते रोज़ दलाल—
बादल है पर बूँद नहीं, कैसी ऋतु की चाल॥
रिश्तों के आकाश में, छाए काले मेघ।
प्रेम न बरसा एक भी, बढ़ते रहे विद्वेष॥
मन की बंजर भूमि पर, उगते केवल जाल—
बादल है पर बूँद नहीं, कैसी ऋतु की चाल॥
सपनों के आकाश में, उड़ते रहे ख्याल।
मेहनत फिर भी ढूँढ़ती, खुशियों का मधुमास॥
आशा का दीपक जले, टूटे हर जंजाल—
बादल है पर बूँद नहीं, कैसी ऋतु की चाल॥
'सौरभ' केवल बोल से, कब बदलें हालात।
बरसें कर्मों की घटा, तब महकें जज़्बात॥
सेवा, प्रेम, विश्वास से, भर जाए हर थाल—
बादल है पर बूँद नहीं, कैसी ऋतु की चाल॥

›› **डॉ. सत्यवान सौरभ**

ईरान कैसे बना महाशक्ति

➲ तनवीर जाफ़री

ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपना निजी मकान तक नहीं ख़रीदा। ईरान के मंत्रियों और शीर्ष सैन्य अधिकारीयों व अन्य आला अफ़सरों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करने नहीं जाते। ईरानी सरकार का कोई भी सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी विदेशी बैंकों में पैसे जमा नहीं कर सकते। ईरान का कोई भी मंत्री,जनरल या उच्चाधिकारी देश के बाहर कोई दूसरा मकान नहीं बनाता। ईरान के सुप्रीम लीडर बिना दिखावे व प्रचार के रोज़ाना 18 घंटे काम करते हैं। वहां कोई भी अमेरिकन या यूरोपीय शिक्षण संस्थान नहीं हैं। ईरान में साक्षरता दर 97 प्रतिशत है क्योंकि शिक्षा मुफ़्त है। इसीलिये वहां के अधिकांश लोग डॉक्टर इंजीनियर,प्रोफ़ेसर आदि हैं जिसका साक्षात नतीजा ईरान ने पिछले युद्ध के दौरान अपनी ड्रोन व मिसाईल क्षमता को साबित कर दुनिया को दिखा भी दिया।

अमेरिका, इज़राइल द्वारा ईरान पर जून 2025 में 12 दिन का और उसके बाद 28 फरवरी 2026 को लगभग 40 दिन का युद्ध थोपा गया था। अचानक थोपे गये इस युद्ध में हालांकि ईरान को जान व माल का काफ़ी नुक़सान हुआ परन्तु ईरान ने भी परमाणु शक्ति संपन्न हुये बिना ही इन दोनों परमाणु शस्त्र संपन्न देशों को ऐसा करारा जवाब दिया कि आख़िरकार स्वयं को विश्वविजेता कहलाने वाले अमेरिका को युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने पड़े। इतने कम समय के युद्ध में अमेरिका व इस्राईल को इतना नुक़्सान पहले कभी नहीं उठाना पड़ा। आज अमेरिका से लेकर इस्राईल तक की जनता यह स्वीकार कर रही है कि इस युद्ध में हर मोर्चे पर ईरान ही विजेता रहा है । क्योंकि ईरान अमेरिका द्वारा युद्धोपरांत हस्ताक्षर किये गये सहमति पत्र में स्वीकार की गयी अधिकांश बातें ईरान के हक़ में तथा ईरान को फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। हालांकि अमेरिका द्वारा पुनः युद्धविराम के समझौते का उल्लंघन कर ईरान पर कई बड़े हमले करने व ईरान द्वारा भी कुवैत व बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कड़ी जवाबी कार्रवाई करने के समाचार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि लगभग 50 वर्षों से वैश्विक प्रतिबंधों का भी सामना करने वाले इस देश ने अत्यंत सीमित संसाधनों के बावजूद अमेरिका व इज़राइल जैसे शक्तिशाली,चालबाज़ व छल कपट में माहिर देशों का एक साथ मुक़ाबला कैसे किया ?

इसमें कोई संदेह नहीं कि ईरानी लोग मुसलमानों के उस शिया वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं जो हज़रत अली,हज़रत इमाम हुसैन व करबला की उस घटना से प्रेरणा लेते हैं जो असत्य,अन्याय व अत्याचार के आगे कभी सर न झुकाने की सीख देती है। इसके साथ साथ ईरान ने धरातल पर जो दूरगामी व सधी हुई रणनीति अपनाई उसी ने ईरान को न केवल अमेरिका व इस्राईल जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों पर विजय दिलाई बल्कि ईरान को विश्व की महाशक्तियों की सूची में भी शामिल कर दिया। अमेरिका व इस्राईल की नाराज़गी के भय से पूरे युद्ध के दौरान आधिकारिक रूप से किसी भी देश ने ईरान की सहायता नहीं की न ही ईरान ने खाने-पीने की चीज़ों व दवाईयों तक के लिये कोई अपील जारी की। युद्ध शुरू होते ही रोटी, पेट्रोल और डीज़ल ईरानियों के लिये निःशुल्क कर दिए गए ताकि उन्हें युद्ध के बोझ का एहसास न हो। अमेरिकी व इस्राईली भीषण बमबारी के बावजूद, एक भी ईरानी नागरिक ने पलायन नहीं किया हाँ विदेशों में रहने वाले हज़ारों ईरानी अपने देश की रक्षा की ग़रज़ से स्वदेश वापस ज़रूर लौटे। युद्ध के दौरान, कई प्रमुख मंत्री अमेरिका विरोधी प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों के साथ निडर होकर सारी सारी रात सड़कों पर नज़र आये। हद तो यह है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकीयान स्वयं बाज़ारों में जाकर वस्तुओं के मूल्य व जनसुविधाओं का जायज़ा लेते नज़र आये ।

सवाल यह है कि ईरान के लोगों व वहाँ के नेतृत्व में इतना दृढ़ विश्वास आया कहाँ से ? तो आइये नज़र डालते हैं कुछ उन छोटी छोटी सामान्य बातों पर जिसे भले ही दुनिया के अधिकांश देशों के लोग व वहाँ का नेतृत्व सम्मान या सम्पन्नता की नज़रों से क्यों न देखते हों परन्तु ईरान के लोगों ने इनसे दूर रहना ही राष्ट्रहित में समझा। मिसाल के तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपना निजी मकान तक नहीं ख़रीदा। ईरान के मंत्रियों और शीर्ष सैन्य अधिकारीयों व अन्य आला अफ़सरों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करने नहीं जाते। ईरानी सरकार का कोई भी सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी विदेशी बैंकों में पैसे जमा नहीं कर सकते। ईरान का कोई भी मंत्री,जनरल या उच्चाधिकारी देश के बाहर कोई दूसरा मकान नहीं बनाता। ईरान के सुप्रीम लीडर बिना दिखावे व प्रचार के रोज़ाना 18 घंटे काम करते हैं। वहां कोई भी अमेरिकन या यूरोपीय शिक्षण संस्थान नहीं हैं। ईरान में साक्षरता दर 97 प्रतिशत है क्योंकि शिक्षा मुफ़्त है। इसीलिये वहां के अधिकांश लोग डॉक्टर इंजीनियर,प्रोफ़ेसर आदि हैं जिसका साक्षात नतीजा ईरान ने पिछले युद्ध के दौरान अपनी ड्रोन व मिसाईल क्षमता को साबित कर दुनिया को दिखा भी दिया।

तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वहां जनता की जेब काटने जैसी कोई टैक्स व्यवस्था नहीं है। यदि परिस्थितिवश वहां मूलयवृद्धि होती भी है तो दूसरी तरफ़ सुप्रीम लीडर के बजट से लोगों को साथ साथ उतनी ही राहत भी दी जाती है। वहां महिलायें कम्युनिटी प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। प्रसव निःशुल्क हैं, साथ ही बच्चे के जन्म पर मां के खाते में कम से कम 20,000 रू का उपहार भी भेजा जाता है। प्रत्येक इलाज का 70% सरकार देती है, जबकि 30% मरीज़ देता है। चोरी, डकैती,बेईमानी,बलात्कार जैसे अपराध बिल्कुल नहीं है। चंदा या दान चोरी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहां रॉयल कल्चर या प्रोटोकॉल जैसी कोई चीज़ नहीं है। ईरान भिखारी रहित देश है। वहां के नियमानुसार पुलिस सूर्यास्त से सूर्योदय तक किसी अपराधी के घर में नहीं घुस सकती क्योंकि वह समय उसकी पत्नी और बच्चों का होता है। वहाँ की जेलें ख़ाली हैं, और अगर कोई अपराधी जेल जाता भी है, तो उसे जेल में काम दिया जाता है, जिसकी तंख़्वाह/मज़दूरी उसके घर भेजी जाती है ताकि उसके परिवार के लोग पैसों के अभाव में किसी अपराध में शामिल न हों।

ईरान में धर्म जाति जैसी कोई विसंगति नहीं है इसलिये कभी साम्प्रदायिक व जातीय दंगे नहीं होते। छुआछूत जादू टोना जैसी कोई प्रथा नहीं है। यहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले व उनके अनेक पूजा स्थल हैं, धर्म के मामलों में सभी को पूरी आज़ादी है। यहां अध्यापकों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। घरेलू नौकर रखने का यहाँ चलन नहीं है। अपने सभी घरेलू काम स्वयं करने पड़ते हैं।

इतने अंततर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद यहाँ के लोगों के चेहरों पर हंसी मुस्कान व संतोष नज़र आता है। कोई भी व्यक्ति चिढ़ा कुढ़ा या ग़ुस्से में नज़र नहीं आता। ईरानियों के इसी स्वभाव हौसले,जज़्बे,कुर्बानी व उनके ईमान की वजह से ही दुनिया के तमाम देश जहाँ अमेरिका व इस्राईल से नफ़रत करने लगे हैं बल्कि वे ईरान से प्यार भी कर रहे हैं व उनका साथ भी दे रहे हैं। इन्हीं व इन जैसे अनेक कारणों की वजह से ही लगभग 50 वर्षों से वैश्विक प्रतिबंध झेलने व अमेरिका जैसी महाशक्ति से लोहा लेने वाला देश आज न केवल 'विजेता ' बनकर उभरा है बल्कि इसने विश्व की महाशक्तियों में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है।

डिग्री से दक्षता की दिशा : शिक्षा संस्थानों में स्वाभिमानी स्वावलंबन का शुभारंभ

➲ डॉ. शैलेश शुक्ला

भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाला राष्ट्र है। देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जनसांख्यिकीय स्थिति भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करती है। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है और यदि उसे उचित शिक्षा, कौशल तथा अवसर प्राप्त हों तो वह राष्ट्र को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है। किंतु विडंबना यह है कि आज भारत में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा डिग्रियाँ प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगारी, असुरक्षा और निराशा का सामना कर रहे हैं। इसका मूल कारण शिक्षा व्यवस्था का वह स्वरूप है, जो विद्यार्थियों को केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने और प्रमाणपत्र प्राप्त करने तक सीमित कर देता है, जबकि वर्तमान समय की आवश्यकता ज्ञान के साथ-साथ दक्षता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा संस्थान डिग्री प्रदान करने वाले केंद्र मात्र न बनें, बल्कि वे युवाओं को स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और दक्ष नागरिक बनाने वाले सशक्त संस्थान बनें।

परंपरागत शिक्षा व्यवस्था लंबे समय तक इस धारणा पर आधारित रही कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों को सहज रूप से रोजगार प्राप्त हो जाएगा। किंतु वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति और बदलते आर्थिक परिदृश्य ने रोजगार की प्रकृति को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। आज केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान, डिजिटल दक्षता, टीम भावना, नवाचार और व्यावहारिक अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश देश के अनेक शिक्षण संस्थानों में अभी भी रटंत प्रणाली, परीक्षा-केंद्रित शिक्षण और सैद्धांतिक ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है। परिणामस्वरूप लाखों विद्यार्थी डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय है।

आज का युग ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का युग है, जिसमें कौशल और नवाचार को विशेष महत्व प्राप्त है। कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence), मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा विज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और स्टार्टअप संस्कृति ने रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। ऐसे में शिक्षा संस्थानों को समयानुकूल पाठ्यक्रम विकसित करने होंगे। विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण, उद्योगों से जुड़ाव, परियोजना-आधारित अधिगम तथा वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रेरित करना होगा। यदि शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों में नवाचार की भावना विकसित करें, तो वे केवल रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले भी बन सकते हैं।

स्वावलंबन की अवधारणा भारतीय चिंतन का मूल आधार रही है। महात्मा गांधी ने 'नई तालीम' के माध्यम से शिक्षा को श्रम, कौशल और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर बल दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए और समाज के प्रति उत्तरदायी भी बनाए। आज के संदर्भ में गांधीजी का यह विचार और भी प्रासंगिक हो गया है।

अग्नि-जाल में बदलते शहरी भवन

➲ डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत आज विश्व के सबसे तेज़ी से शहरीकरण करने वाले देशों में शामिल है। आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, सेवा क्षेत्र के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर निरंतर हो रहे पलायन ने भारतीय शहरों का स्वरूप तेजी से बदला है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक बहुमंजिला इमारतें, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, कोचिंग संस्थान, होटल, अस्पताल और मिश्रित-उपयोग (Mixed-Use) वाले भवन विकास के नए प्रतीक बनकर उभरे हैं। किंतु इस विकास के पीछे एक गंभीर सच्चाई भी छिपी है—शहरी नियोजन की अनदेखी, सुरक्षा मानकों की उपेक्षा और प्रशासनिक शिथिलता। परिणामस्वरूप, आज अनेक शहरी भवन आर्थिक प्रगति के केंद्र होने के साथ-साथ संभावित ₹अग्नि-जाल₹ भी बनते जा रहे हैं।

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अग्नि-दुर्घटनाओं ने इस संकट की भयावहता को उजागर किया है। दिल्ली के कोचिंग संस्थानों, सूरत के कोचिंग सेंटर, कोलकाता के होटल, हैदराबाद की व्यावसायिक इमारतों, मुंबई के अस्पतालों और अनेक बाजारों में लगी आग ने सैकड़ों परिवारों को असमय शोक में डुबो दिया। अधिकांश घटनाओं में एक जैसी कमियाँ सामने आईं—भवनों का अनधिकृत उपयोग, अग्नि-सुरक्षा उपकरणों का अभाव, बंद या अवरुद्ध आपातकालीन निकास, संकरी सड़कें, अवैध पार्किंग और नियमों के पालन में गंभीर लापरवाही। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या किसी एक भवन, किसी एक शहर या किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि हमारे पूरे शहरी विकास मॉडल की है।

भारत में मिश्रित-उपयोग वाले भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक ही भवन में नीचे दुकानें, ऊपर कार्यालय, उसके ऊपर कोचिंग संस्थान और सबसे ऊपर आवास होना अब सामान्य बात है। यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से लाभकारी अवश्य प्रतीत होती है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जोखिमपूर्ण है। ऐसे भवनों में ज्वलनशील सामग्री, विद्युत उपकरण, गैस सिलेंडर, बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति और सीमित निकास मार्ग आग लगने की स्थिति में उसे विनाशकारी बना देते हैं। यदि भवन मूल रूप से आवासीय उद्देश्य के लिए निर्मित हो और बाद में बिना संरचनात्मक परिवर्तन के व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाए, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

अनियोजित शहरीकरण इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। भारत के अधिकांश शहर बिना दीर्घकालिक मास्टर प्लान के फैलते गए। आबादी बढ़ती गई, लेकिन सड़कें नहीं बढ़ीं; भवन ऊँचे होते गए, परंतु अग्निशमन सेवाओं की क्षमता उसी अनुपात में विकसित नहीं हुई। अनेक पुराने बाजारों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन तक प्रवेश नहीं कर पाते। कई स्थानों पर बिजली के तारों का जाल, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण आग पर नियंत्रण की प्रक्रिया को और कठिन बना देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कुछ ही मिनटों में छोटी आग भी बड़ी त्रासदी में बदल जाती है।

इस संकट का दूसरा महत्वपूर्ण कारण नीतिगत विरोधाभास है। एक ओर सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनुमतियों की प्रक्रिया सरल बना रही है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर पर्याप्त बल नहीं दिया जा रहा।

कई राज्यों में निश्चित ऊँचाई तक के भवनों को अनिवार्य अग्नि-अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Fire NOC) से छूट प्राप्त है। परिणामस्वरूप हजारों ऐसे भवन बिना नियमित अग्नि-सुरक्षा निरीक्षण के संचालित होते रहते हैं। कई बार भवन निर्माण की अनुमति एक उद्देश्य के लिए मिलती है, किंतु समय के साथ उसका उपयोग पूरी तरह बदल जाता है। दुर्भाग्य से इस परिवर्तन की प्रभावी निगरानी करने वाली कोई मजबूत प्रणाली विकसित नहीं हो सकी है।

प्रशासनिक समन्वय का अभाव भी स्थिति को जटिल बनाता है। भवन निर्माण की अनुमति नगर निगम देता है, भूमि उपयोग परिवर्तन विकास प्राधिकरण देखता है, व्यापार लाइसेंस किसी अन्य विभाग से जारी होता है और अग्नि-सुरक्षा का दायित्व अग्निशमन विभाग पर होता है। इन विभागों के बीच सूचनाओं का समुचित आदान-प्रदान नहीं होने से नियमों का प्रभावी अनुपालन नहीं हो पाता। कई बार भवन निर्माण के समय सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली जाती हैं, लेकिन बाद में भवन में किए गए अवैध परिवर्तन वर्षों तक किसी की निगाह में नहीं आते।

भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव भी इस समस्या का महत्वपूर्ण पहलू है। यदि निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित रह जाएँ और प्रमाण-पत्र वास्तविक जाँच के बिना जारी होने लगें, तो नियमों का अस्तित्व मात्र औपचारिकता बनकर रह जाता है।

अनेक दुर्घटनाओं के बाद यह सामने आया कि भवनों में अग्निशामक यंत्र तो लगे थे, किंतु उनकी समय-समय पर जाँच नहीं हुई थी। कई स्थानों पर स्प्रिंकलर प्रणाली कार्य नहीं कर रही थी या आपातकालीन निकास पर ताले लगे हुए थे। यह केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि प्रशासनिक और नैतिक विफलता भी है।

नागरिक जागरूकता की कमी भी इस संकट को बढ़ाती है। अधिकांश लोग भवन खरीदते या किराए पर लेते समय अग्नि-सुरक्षा व्यवस्था की जाँच नहीं करते। व्यापारिक प्रतिष्ठान लागत कम करने के लिए सुरक्षा उपकरणों की उपेक्षा करते हैं। नियमित मॉक ड्रिल, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और आपातकालीन निकासी अभ्यास को अनावश्यक समझा जाता है। जबकि विकसित देशों में अग्नि-सुरक्षा संस्कृति (Fire Safety Culture) को विद्यालय स्तर से ही बढ़ावा दिया जाता है।

भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था पिछले दो दशकों में काफी मजबूत हुई है, लेकिन आग जैसी शहरी आपदाओं की रोकथाम पर अपेक्षित ध्यान अभी भी नहीं दिया गया है। आपदा आने के बाद राहत और बचाव कार्यों में हमारी संस्थाएँ उल्लेखनीय कार्य करती हैं, किंतु यदि रोकथाम और जोखिम न्यूनीकरण पर समान गंभीरता से निवेश किया जाए तो अनेक त्रासदियों को रोका जा सकता है। आपदा प्रबंधन का मूल सिद्धांत भी यही है कि रोकथाम पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया राहत और पुनर्वास पर होने वाले कई गुना व्यय को बचाता है।

अब आवश्यकता केवल दंडात्मक कार्रवाई की नहीं, बल्कि व्यापक संरचनात्मक सुधारों की है। सबसे पहले शहरी नियोजन को वैज्ञानिक और भविष्य-दृष्टि वाला बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक शहर में भूमि उपयोग, जनसंख्या घनत्व, सड़क चौड़ाई, जल स्रोत, अग्निशमन केंद्रों की स्थिति और आपातकालीन पहुँच मार्गों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। मिश्रित-उपयोग वाले क्षेत्रों के लिए अलग सुरक्षा मानक निर्धारित किए जाएँ और भवनों की स्वीकृति इन्हीं मानकों के अनुरूप हो।

दूसरा, राष्ट्रीय भवन संहिता तथा अग्नि-सुरक्षा मानकों का देशभर में समान रूप से कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भवन की ऊँचाई के बजाय उसमें उपस्थित लोगों की संख्या, गतिविधि की प्रकृति और अग्नि-जोखिम के आधार पर सुरक्षा मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। सभी सार्वजनिक और मिश्रित-उपयोग भवनों में स्वचालित स्प्रिंकलर, धुआँ संवेदक, अग्नि-अलार्म, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और स्पष्ट निकास मार्ग अनिवार्य हों।

तीसरा, भवनों की स्वीकृति, व्यापार लाइसेंस, Fire NOC और निरीक्षण को एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाए। यदि किसी भवन का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य से भिन्न पाया जाए या उसका सुरक्षा प्रमाण-पत्र समाप्त हो जाए तो संबंधित विभागों को स्वतः सूचना प्राप्त हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग कर जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।

चौथा, अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक उपकरण, ऊँची इमारतों तक पहुँचने वाली हाइड्रोलिक सीढ़ियाँ, पर्याप्त जल स्रोत, प्रशिक्षित मानव संसाधन और तेज़ प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की जाए। छोटे और मध्यम शहरों में भी अग्निशमन अवसंरचना को जनसंख्या और भवनों की संख्या के अनुरूप मजबूत किया जाना चाहिए।

पाँचवाँ, नागरिक सहभागिता को नीति का अभिन्न अंग बनाया जाए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, बाजारों, अस्पतालों और आवासीय सोसाइटियों में नियमित अग्नि-सुरक्षा प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल अनिवार्य किए जाएँ। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान ने जनभागीदारी को बढ़ावा दिया, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर अग्नि-सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

अंततः, शासन व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी दुर्घटना का कारण नियमों का उल्लंघन या निरीक्षण में लापरवाही हो, तो केवल भवन मालिक ही नहीं बल्कि संबंधित अधिकारियों की भी स्पष्ट जवाबदेही तय हो। पारदर्शिता, नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षण और स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकते हैं।

भारत के शहर केवल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, सपनों और भविष्य के आधार हैं। यदि शहरी विकास सुरक्षा, नियोजन और उत्तरदायित्व से रहित होगा, तो विकास का यही मॉडल बार-बार मानवीय त्रासदियों को जन्म देता रहेगा। आवश्यकता ऐसी शहरी संस्कृति विकसित करने की है जिसमें भवनों की ऊँचाई से अधिक महत्व उनकी सुरक्षा को मिले, व्यावसायिक लाभ से अधिक प्राथमिकता मानव जीवन को दी जाए और नियमों का पालन बाध्यता नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाए।

वास्तविक स्मार्ट सिटी वही होगी जहाँ नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, जहाँ भवन विकास के प्रतीक होने के साथ-साथ सुरक्षा के भी मानक बनें और जहाँ प्रत्येक निर्माण यह संदेश दे कि मानव जीवन किसी भी आर्थिक लाभ से अधिक मूल्यवान है। यदि भारत को भविष्य के सुरक्षित, टिकाऊ और आपदा-प्रतिरोधी शहर बनाने हैं, तो प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयों से आगे बढ़कर दूरदर्शी शहरी नियोजन, कठोर नियामकीय व्यवस्था, आधुनिक तकनीक, पारदर्शी प्रशासन और जागरूक नागरिक सहभागिता पर आधारित दीर्घकालिक सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। तभी विकास की चमक के पीछे छिपे अग्नि-जाल को समाप्त कर सुरक्षित और संवेदनशील शहरी भारत का निर्माण संभव होगा।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

दिल्ली मेट्रो को वैश्विक सम्मान

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली मेट्रो रेल निगम को सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। निगम को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन संघ द्वारा परिचालन उत्कृष्टता श्रेणी में उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

दिल्ली मेट्रो को यह सम्मान यात्रियों के लिए विकसित की गई स्मार्ट घर-से-गंतव्य यात्रा सेवा के लिए प्रदान किया गया है। इस सेवा के माध्यम से यात्रियों को प्रथम और अंतिम पड़ाव संपर्क, वास्तविक समय की जानकारी तथा निर्बाध टिकट व्यवस्था जैसी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो रही हैं।

निगम का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित 'सारथी' अनुप्रयोग यात्रियों को पूरी यात्रा की योजना बनाने और एकीकृत किराया भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे यात्रा अधिक सरल और सुविधाजनक बनी है।

यह सम्मान समारोह 23 जून को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया, जहां निदेशक परिचालन एवं सेवाएं डॉ. अमित कुमार जैन तथा अतिरिक्त महाप्रबंधक परिचालन रजनीश राणा ने पुरस्कार प्राप्त किया।

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी।

मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ अधिकतम तापमान करीब 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

सुबह साढ़े आठ सापेक्ष आर्द्रता 56 प्रतिशत दर्ज की गई।

समीर ऐप के अनुसार, सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 157 दर्ज किया गया जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है।

सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' माना जाता है।

समाजसेवी एवं सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त विद्या प्रकाश का निधन

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। शाहदरा के बलबीर नगर क्षेत्र की पहचान माने जाने वाले दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त एवं प्रख्यात समाजसेवी विद्या प्रकाश शर्मा का रविवार को निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

विद्या प्रकाश शर्मा पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से बलबीर नगर विस्तार में अपने परिवार के साथ निवास कर रहे थे। सरकारी सेवा के साथ-साथ उनकी सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि थी और जीवन के अंतिम समय तक वह समाजसेवा में सक्रिय रहे। अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

सरल, सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण विद्या प्रकाश शर्मा ने क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। लोगों की सहायता करना और सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेना उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान थी। वह अपने पीछे पुत्र, पुत्री तथा उनके परिवार सहित एक बड़ा भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं।

आईपी यूनिवर्सिटी के एमपीओ प्रोग्राम की ऑफलाइन काउंसलिंग 1 जुलाई को

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। आईपी यूनिवर्सिटी के एमपीओ प्रोग्राम में दाख़िले के लिए पहली ऑफलाइन काउंसलिंग 1 जुलाई को द्वारका कैंपस में आयोजित की जाएगी। उसी दिन आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत मेरिट के आधार पर सीटों का भीआवंटन कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के सभी सफल उम्मीदवार इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग के दिन यूनिवर्सिटी कुलसचिव के नाम से निर्गत 96 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट, चार पासपोर्ट आकार के फोटो, सीईटी का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, ऑनलाइन भरा हुआ फार्म,जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, इत्यादि साथ लाना हैं। अन्यथा 109 कोड वाले इस प्रोग्राम की काउंसलिंग के बाद आवंटित सीट 7 जुलाई तक निरस्त किए जा सकते हैं। यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से संबद्ध आईएसआईसी इंस्टिट्यूट में 8 सीटें उपलब्ध है।इस काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी आवेदक इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.ipu.ac.in और http://www.ipu.admissions.nic.in देख सकते हैं।

रसोईघरों से गैस सिलिंडर चुराने वाला गिरोह पकड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर क्षेत्र में घरों के रसोईघरों से एलपीजी गैस सिलिंडर चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 10 गैस सिलिंडर तथा वारदात में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन बरामद किया है। मुख्य आरोपी के विरुद्ध पहले से भी अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पिछले कई महीनों से सागरपुर क्षेत्र में घरों से एलपीजी गैस सिलिंडर चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही थी। गैस सिलिंडरों की कमी को देखते हुए इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए विशेष दल का गठन किया गया था।

जांच के दौरान तकनीकी निगरानी तथा विभिन्न स्थानों पर लगे निगरानी उपकरणों की सहायता से पुलिस ने 24 जून को डाबड़ी गोलचक्कर के निकट नाला मार्ग से निहाल विहार निवासी दीपक उर्फ दीपु को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से दो चोरी के गैस सिलिंडर और वारदात में प्रयुक्त दुपहिया वाहन बरामद किया गया।

भाजपा मयूर विहार जिला उपाध्यक्ष बनने पर मोहित शर्मा को मिल रहीं बधाइयां

नई दिल्ली, 28 जून (वेब वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी के मयूर विहार जिला में मोहित शर्मा को पुनः जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विभिन्न पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए संगठन के प्रति उनके समर्पण और नेतृत्व क्षमता की सराहना की है।

इंद्रेश शर्मा ने मोहित शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान उनके नेतृत्व, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मोहित शर्मा संगठन और समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा उनका कार्यकाल सफल और गौरवपूर्ण रहेगा।

इस अवसर पर न्यू अशोक नगर मंडल से जिला उपाध्यक्ष पद पर चुने गए विशाल चौधरी को भी कार्यकर्ताओं ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यकर्ताओं ने उनके उज्ज्वल और सफल कार्यकाल की कामना करते हुए विश्वास जताया कि वह संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भारतीय जनता पार्टी न्यू अशोक नगर मंडल के प्रवक्ता कृष्णा सिंह ने मोहित शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि संगठन के प्रति उनका समर्पण, अथक परिश्रम और नेतृत्व क्षमता संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मोहित शर्मा सदैव राष्ट्रहित, जनसेवा और संगठन की विचारधारा को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहे हैं और भविष्य में भी उनका योगदान संगठन के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

जिला उत्तर पश्चिम के भाजपा जिला महामंत्री राहुल जगदीश हांडा, गिरीशचंद्र वर्मा तथा भाजपा न्यू अशोक नगर मंडल के सामाजिक माध्यम प्रमुख संदीप मित्तल सहित अनेक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी मोहित शर्मा को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

'क्लीन दिल्ली विद सीएम' हर रविवार चलेगा स्वच्छता अभियान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया श्रमदान

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को चिल्ला गांव स्थित यमुना घाट पर आयोजित 'क्लीन दिल्ली विद सीएम' स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए स्वयं श्रमदान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवक, सामाजिक संगठन तथा स्थानीय नागरिक भी अभियान से जुड़े। मुख्यमंत्री ने घाट पर सफाई कर लोगों को स्वच्छ यमुना के लिए जनभागीदारी का संदेश दिया।

इस अवसर पर रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की संस्कृति, स्मृति और जीवनधारा है। उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। उन्होंने कहा कि सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रही यमुना आज प्रदूषण की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है, जिससे निपटने के लिए सरकार और समाज को मिलकर कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना के पुनर्जीवन के लिए वैज्ञानिक, स्थायी और व्यापक स्तर पर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सीवेज शोधन संयंत्रों के आधुनिकीकरण, नए विकेंद्रीकृत शोधन संयंत्रों की स्थापना, सीवर नेटवर्क के विस्तार तथा यमुना में गिरने वाले नालों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में कोई भी नाला बिना उपचार के सीधे यमुना में नहीं गिरेगा।

रेखा गुप्ता ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि पूजा सामग्री, प्लास्टिक, निर्माण मलबा और अन्य कचरे को यमुना में प्रवाहित न करें। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पूजा सामग्री और खंडित प्रतिमाओं के सम्मानजनक निस्तारण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेष संग्रह केंद्र स्थापित कर रही है, जहां इनका वैज्ञानिक और व्यवस्थित पुनर्चक्रण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जनसहभागिता को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से अब प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान, यमुना सफाई अभियान अथवा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से इन अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवकों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े युवाओं से संवाद भी किया। स्वयंसेवकों ने सुझाव दिया कि एकत्रित प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर विद्यालयों के लिए बेंच, कूड़ादान तथा अन्य उपयोगी सामग्री तैयार की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने इस नवाचारी पहल की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे प्रयासों को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर यमुना संरक्षण अभियान से जुड़ा है और अपने अवकाश के समय में भी नदी की सफाई तथा जनजागरूकता के लिए कार्य करता है। मुख्यमंत्री ने ऐसे युवाओं के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यही युवा शक्ति स्वच्छ भारत और स्वच्छ यमुना अभियान की सबसे बड़ी ताकत है।

मुख्यमंत्री ने अभियान में शामिल सभी स्वयंसेवकों और सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनभागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से यह अभियान एक व्यापक जनआंदोलन का रूप लेगा और दिल्ली को स्वच्छ, हरित तथा विकसित राजधानी बनाने के संकल्प को नई दिशा मिलेगी।

नितिन नवीन के साथ हर्ष मल्होत्रा ने सुना प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 135वें संस्करण को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों तथा पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यालय के कर्मचारियों के साथ सुना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं सांसद अनिल बलूनी तथा सह मीडिया प्रमुख संजय मयूख भी उपस्थित रहे। वहीं, राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद तरुण चुघ ने ईस्ट पटेल नगर में स्थानीय नागरिकों, आवासीय कल्याण संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना।

सांसद मनोज तिवारी ने नवीन शाहदरा में विधायक जितेन्द्र महाजन एवं जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की, जबकि सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक विशेष आयोजन में गणमान्य लोगों के साथ 'मन की बात' सुनी। संगठन महामंत्री पवन राणा, सांसद योगेन्द्र चांदोलिया, वीरेन्द्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय तथा राजन तिवारी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भी विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों के साथ कार्यक्रम सुना।

इस अवसर पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास, पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक सहभागिता तथा पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध परम्पराओं पर प्रेरणादायी विचार रखे। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन द्वारा अपने निवास पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आमंत्रित कर कार्यक्रम सुनना भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार के रूप में प्रस्तुत करता है।

हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली में 8367 बूथों पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना।

'जलेबी' देने में देरी से नाराज हो कर विक्रेता को गोली मारने वाले को उम्रकैद

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

दिल्ली में कतार में लगे दूसरे लोगों से पहले 'जलेबी' नहीं देने से नाराज होकर मिठाई विक्रेता को गोली मारने के जुर्म में अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

यह घटना 12 वर्ष पहले की है। बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक मिठाई की दुकान पर,18 फरवरी 2014 को जब विक्रेता ने क्रम तोड़ने से मना किया, तो आरोपी ने उसे थप्पड़ मारा, अपनी पिस्तौल निकाली और बेहद नजदीक से उसके सिर में गोली मार दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र राणा, नीरज को सजा सुनाने के मामले में दलील सुन रहे थे।

नीरज को इसी महीने की शुरुआत में भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और हथियारों के गैर-कानूनी इस्तेमाल के लिए हथियार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।

न्यायाधीश ने आठ जून के आदेश में कहा, ''रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि दोषी का विक्रेता के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि वह चाहता था कि लाइन में खड़े दूसरे ग्राहकों से पहले उसे जलेबी दी जाए। जब विक्रेता ने ऐसा करने से मना किया, तो दोषी ने उसे थप्पड़ मारा, पिस्तौल निकाली और बहुत पास से उसके सिर में गोली मार दी।''

उन्होंने बताया कि विक्रेता को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई , नीरज को घटनास्थल के पास से पकड़ा गया साथ ही उसके पास से हथियारों का एक नकली लाइसेंस भी बरामद हुआ।

न्यायाधीश ने कहा, ''मैंने इस मामले से जुड़ी नरमी बरतने वाली परिस्थितियों पर विचार किया है। दोषी किसी दूसरे मामले में शामिल नहीं है। वह पूरी सुवनाई के दौरान हिरासत में रहा। वह समाज के लिए खतरा नहीं है और उसके सुधरने की संभावना है।''

उन्होंने कहा, '' इसलिए, यह मामला 'दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में नहीं आता। दोषी 2014 से सुनवाई का सामना कर रहा है और उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे हैं।'' इसके बाद उन्होंने दोषी को हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

विकसित भारत प्रबुद्ध सम्मेलन में विकसित राष्ट्र के संकल्प पर हुआ मंथन

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कुंडली विधानसभा क्षेत्र में ₹विकसित भारत प्रबुद्ध सम्मेलन₹ का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया।

न्यू अशोक नगर के निगम पार्षद संजीव सिंह ने सम्मेलन में सहभागिता करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और जनकल्याण को समर्पित रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में विकसित भारत के निर्माण में समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता को आवश्यक बताते हुए राष्ट्रहित में कार्य करने का आह्वान किया।

सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विकासोन्मुख दृष्टिकोण की भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने विकसित दिल्ली और विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और उसे साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा, जिले के विभिन्न पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।

जेएनयू में पीजी दाखिले की दूसरी मेरिट सूची तीन जुलाई को

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर (पीजी) और एडीओपी के दाखिले का पहला चरण पूरा हो चुका है। विश्वविद्यालय के अनुसार दूसरी मेरिट सूची तथा सुपरन्यूमेरेरी सीटों के लिए सूची तीन जुलाई को जारी की जाएगी। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को तीन से पांच जुलाई तक पंजीकरण और शुल्क भुगतान करना होगा। चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नौ, 10, 13, 14, 15, 16 और 17 जुलाई को किया जाएगा।

रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया

रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों से अंतिम बार रुचि अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस) 23 से 25 जुलाई तक मांगी जाएगी। इसके बाद अंतिम मेरिट सूची 31 जुलाई को जारी होगी। अंतिम सूची के अभ्यर्थियों को 31 जुलाई से दो अगस्त तक शुल्क जमा कर सीट सुरक्षित करनी होगी। अंतिम सूची के चयनित विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन छह और सात अगस्त को होगा। विश्वविद्यालय ने 10 अगस्त, 2026 को प्रवेश और पंजीकरण की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

आईपीयू काउंसलिंग प्रक्रिया

आईपीयू के बीए(लिबरल आर्ट्स) प्रोग्राम की ऑफलाइन काउंसलिंग 2 जुलाई को आईपी यूनिवर्सिटी के बीए (लिबरल आर्ट्स) प्रोग्राम में दाखिले के लिए पहली ऑफलाइन काउंसलिंग 2 जुलाई को द्वारका कैंपस में आयोजित की जाएगी। उसी दिन आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत मेरिट के आधार पर सीटों का भी आवंटन कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के सभी सफल उम्मीदवार इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।

काउंसलिंग के दिन यूनिवर्सिटी कुलसचिव के नाम से निर्गत 96 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट, चार पासपोर्ट आकार के फोटो, सीईटी का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, ऑनलाइन भरा हुआ फ़ॉर्म,जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, इत्यादि साथ लाना हैं। 461 कोड वाले इस प्रोग्राम की काउंसलिंग के बाद आवंटित सीट 9 जुलाई तक निरस्त किए जा सकते हैं। यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा यूनिवर्सिटी से संबद्ध कुछ इंस्टिट्यूट में भी उपलब्ध है।

जानकारी के लिए वेबसाइट

इस काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी आवेदक इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.ipu.ac.in और http://www.ipu.admissions.nic.in पर जा सकते हैं।

डीयू में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया और शुल्क विवरण

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विश्वविद्यालय ने सामान्य सीट आवंटन प्रणाली पोर्टल को 27 जून से सक्रिय कर दिया है। इसी पोर्टल के माध्यम से सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक 2026 के प्राप्तांकों के आधार पर ही दिया जाएगा। विश्वविद्यालय से संबद्ध 70 से अधिक महाविद्यालयों में संचालित 79 स्नातक पाठ्यक्रमों की लगभग 71 हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश किया जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र 21 जुलाई से प्रारंभ होने की संभावना है।

ऐसे करें आवेदन

प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक 2026 का आवेदन क्रमांक और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद विद्यार्थियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर प्रोफाइल पूर्ण करनी होगी।

प्रोफाइल पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों का चयन करना होगा। सभी विकल्प सावधानीपूर्वक भरने के पश्चात आवेदन पत्र जमा करना होगा। इसके बाद विद्यार्थियों को सीट आवंटन प्रक्रिया की प्रतीक्षा करनी होगी।

पंजीकरण शुल्क निर्धारित

विश्वविद्यालय ने विभिन्न वर्गों के लिए पंजीकरण शुल्क भी निर्धारित किया है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 रुपये शुल्क देना होगा।

वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है।

प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण में अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर भरना होगा।

कई चरणों में होगा सीट आवंटन

विश्वविद्यालय की ओर से मेरिट के आधार पर कई चरणों में सीटों का आवंटन किया जाएगा। सीट मिलने के बाद अभ्यर्थी चाहे तो आवंटित सीट को स्थिर कर सकते हैं अथवा उच्च प्राथमिकता वाले महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम के लिए उन्नयन विकल्प का चयन कर अगले चरण का इंतजार कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें और प्रवेश कार्यक्रम तथा अन्य अद्यतन जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।

लेबनान के साथ नया समझौता ईरान के लिए बड़ा झटका : नेतन्याहू

यरुशलम, (वेब वार्ता)। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल और लेबनान के बीच नव हस्ताक्षरित रूपरेखा समझौते को ईरान के लिए बड़ा रणनीतिक झटका करार देते हुए दोहराया है कि जब तक हिजबुल्ला निरस्त्र नहीं हो जाता और इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है, तब तक इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में तैनात रहेंगे।

समझौते में व्यापक रूप से इस बात की पुष्टि की गई है कि हिजबुल्ला और अन्य सशस्त्र समूहों से उत्पन्न खतरा समाप्त होने के बाद इजरायल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुलायेगा तथा कब्जे वाले सभी क्षेत्रों का नियंत्रण लेबनानी सशस्त्र बल (एलएएफ) को सौंप देगा।

पीओके पर पाक रक्षा मंत्री के बयान से विवाद, मानवाधिकार परिषद ने जताई आपत्ति

इस्लामाबाद, (वेब वार्ता)। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान पर विवाद गहरा गया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के रावलाकोट और मीरपुर के निवासियों को "वास्तविक कश्मीरी नहीं" बताया था। इस टिप्पणी के बाद पाकिस्तान के मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) सहित कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

मानवाधिकार परिषद ने अपने बयान में कहा कि संवैधानिक और सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों को पहचान और संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर अत्यंत जिम्मेदारी और सावधानी के साथ टिप्पणी करनी चाहिए। परिषद ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण जारी करने और भविष्य में ऐसी टिप्पणियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

पीओके के राजनीतिक नेता फैसल मुमताज राठौर ने भी रक्षा मंत्री के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपनी पहचान के लिए किसी राजनेता या मंत्री से प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

राठौर ने यह भी कहा कि विवाद बढ़ने के बाद रक्षा मंत्री अपनी मूल टिप्पणी से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने और विवादास्पद बयान पर खेद व्यक्त करने की मांग की।

नेपाल : प्रतिनिधि सभा से वित्त विधेयक पारित, सार्वजनिक ऋण विधेयक पर चर्चा जारी

काठमांडू, (वेब वार्ता)। नेपाल प्रतिनिधि सभा की बैठक में वित्त विधेयक को पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने विधेयक पारित करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे आज संसद की बैठक में बहुमत से मंजूरी मिल गई।

सांसद हरि प्रसाद भुसाल और सुशील खड़का ने अपने संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिए। वहीं, सांसद गंगा लक्ष्मी अवाल, डॉ. पुष्पराज कंडेल, हरका राज राई, पार्वती बीके और नरेन्द्र कुमार केरुङ द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमत से खारिज कर दिए गए। फिलहाल 'सार्वजनिक ऋण विधेयक' पर धारा-दर-धारा चर्चा जारी है।

नेपाल के वित्त मंत्री का दावा : मध्यपूर्व तनाव कम होने के बाद ही घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

काठमांडू, 28 जून (वेब वार्ता)। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि मध्यपूर्व में तनाव कम होने के बाद ही डीजल, पेट्रोल सहित ईंधन के दाम घटने की संभावना है।

प्रतिनिधि सभा की बैठक में रविवार को आर्थिक विधेयक 2083 पर सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मध्यपूर्व की स्थिति सामान्य होने की संभावना है, जिससे ईंधन की कीमतों में भी गिरावट आने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री वाग्ले ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पहले ही घट चुकी है। हालांकि, नेपाल में भारतीय आयल निगम के माध्यम से आयात होने वाले ईंधन की आपूर्ति प्रक्रिया में समय लगने के कारण फिलहाल कीमत घटाने की स्थिति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी।

उन्होंने कहा, "मध्यपूर्व में जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उसके कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा। इस बोझ को कम करने के लिए वित्त मंत्री बनने के दो सप्ताह के भीतर डीजल, पेट्रोल और मिट्टीतेल के आयात पर लगने वाले भंसार शुल्क तथा डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले पूर्वाधार विकास कर में 50 प्रतिशत की छूट दी।"

उन्होंने आगे कहा कि अब मध्यपूर्व की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आ चुकी है। लेकिन कच्चे तेल से तैयार ईंधन बनकर भारतीय आयल निगम के जरिए नेपाल तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। वित्त मंत्री वाग्ले ने दावा किया कि पदभार संभालते ही उन्होंने ईंधन की कीमत घटाने के लिए आवश्यक पहल शुरू कर दी थी।

ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के आठ सैन्य ठिकानों पर किया हमला

तेहरान, (वेब वार्ता)। ईरान ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अमेरिका की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का "करारा जवाब" दिया जाएगा तथा हाल में हुए युद्धविराम समझौते 'इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन' के तहत चल रही सभी कूटनीतिक प्रक्रियाएं स्थगित की जा सकती हैं।

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा कि अमेरिकी हमले युद्धविराम का उल्लंघन हैं और इनके कारण "सभी कूटनीतिक प्रक्रियाएं पूरी तरह रोक दी जाएंगी।"

ईरान के सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी ने आईआरजीसी के हवाले से कहा कि ईरानी नौसेना और एयरोस्पेस बल ने स्थानीय समयानुसार रात दो बजे से तीन बजे के बीच संयुक्त अभियान चलाकर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के आठ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस तथा बहरीन के सलमान बंदरगाह स्थित अमेरिकी पांचवें बेड़े का मुख्यालय शामिल है। ये हमले अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले की घोषणा के कुछ घंटे बाद किये गये। सेंटकॉम ने कहा था कि अमेरिकी सेना ने वाणिज्यिक जहाजरानी के खिलाफ ईरान की कार्रवाई के जवाब में अवसरंचनाओं, संचार प्रणालियों, वायु रक्षा ठिकानों, ड्रोन भंडारण केंद्रों तथा बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता को निशाना बनाया।

सेंटकॉम ने शनिवार को कहा था कि अमेरिकी सैन्य विमानों ने ईरान की सैन्य निगरानी प्रणाली, संचार तंत्र, वायु रक्षा ठिकानों, ड्रोन भंडारण केंद्रों और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता पर हमला किया है। आईआरजीसी ने कड़े शब्दों में जारी बयान में अमेरिका पर युद्धविराम का उल्लंघन करने तथा पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए 'इस्लामाबाद समझौते' के तहत की गयी प्रतिबद्धताओं को तोड़ने का आरोप लगाया।

अमेरिका ने ईरान पर लगातार दसरे दिन बरसाए बम

बहरीन और कुवैत में हवाई हमले के सायरन बजे

➲ तेहरान/वाशिंगटन/बेरूत, (वेब वार्ता)।

चंद दिनों की शांति के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य के पास एक कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर बमबारी की है। अमेरिका ने सिरिक शहर, बंदर-ए-लेंघे और केशम द्वीप को निशाना बनाया है। उधर, बहरीन और कुवैत में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। कुवैत की सेना ने कहा है कि दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। उधर, लेबनान में शांति की उम्मीदें धराशाई हो गई हैं।

लेबनान सरकार के साथ दुश्मनी खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर बमबारी की है। इस बमबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इजराइल के उल्लंघनों को रोकने में मदद मांगी है। उधर, ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ हुए समझौते को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह संप्रभुता का आत्मसमर्पण है।

सीएनएन, अल जजीरा, एबीसी न्यूज और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी मध्य कमान (सेंटकॉम) ने कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने होर्मुज जलडमरूमध्य के अंदर और उसके आस-पास कई जगहों पर हमले किए है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर हमले का एक धुंधला वीडियो भी शेयर किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने हमलों के अपने ताजा दौर में देश के पांच तटीय इलाकों पर बमबारी की।

आईआरजीसी का कहना है कि दुश्मन की किसी भी आक्रामकता का करारा जवाब दिया जाएगा। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका-ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य में आवागमन को नियंत्रित करने की व्यवस्था तेहरान के पास है।

अमेरिका इसका उल्लंघन कर रहा है। और अब से नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों से पहले की तुलना में ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा।

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह हमले इसलिए किए गए क्योंकि ईरान ने ही युद्धविराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स के साथ-साथ तटीय रडार सुविधाओं को भी निशाना बनाया। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिकी सेना ने पनामा के झंडे वाले टैंकर पर ईरान के रात भर चले ड्रोन हमलों के जवाब में ये हमले किए। इस टैंकर में 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल लदा हुआ था।

ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ऐसा समय भी आ सकता है जब अमेरिका मजबूर होकर पूरी ताकत से सैन्य हमला करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उधर, अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सेना को निशाना बनाया है। ईरान की इरना और तस्नीम समाचार एजेंसियों ने आईआरजीसी का एक बयान जारी किया है। इसमें कुवैत और बहरीन पर हुए हमलों की पुष्टि की गई है।

आईआरजीसी ने कहा कि उसकी नौसेना और वायुसेना ने कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन की राजधानी मनामा में पोर्ट सलमान पर मौजूद अमेरिकी पांचवें नौसैनिक बेड़े पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। बयान में कहा गया है कि ये हमले ईरान के पांच तटीय इलाकों पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में किए गए। ओमान ने बहरीन पर हुए कथित ईरानी ड्रोन हमले की निंदा की है।

सनद रहे, फरवरी के आखिर में शुरू यह लड़ाई अब तक नहीं थम सकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य, सरकारी और बुनियादी ढांचों के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इससे मध्य पूर्व में संकट बढ़ गया।

शांति के तमाम प्रयास हुए। इस कड़ी में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट पहुंचे और युद्ध खत्म करने वाले समझौते के लिए बातचीत शुरू की। इस बातचीत का आधार दोनों देशों के बीच पिछले हफ्ते हस्ताक्षरित सहमति-पत्र रहा। यह सिलसिला और आगे बढ़ पाता कि लड़ाई फिर शुरू हो गई।

डॉ. महरंग की सजा के खिलाफ बलोचिस्तान में प्रदर्शन जारी

फैसला सुनाने वाला जज पदोन्नत

➲ इस्लामाबाद, (वेब वार्ता)।

क्वेटा के एंटी-टेररिज्म कोर्ट के लापता बलोचों की आवाज उठाने वालीं डॉ. महरंग बलोच और सिबघतुल्लाह शाह को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के फैसले के खिलाफ बलोचिस्तान में प्रदर्शन जारी हैं। इस बीच फैसला सुनाने वाले जज मोहम्मद अली मुबीन को बलोचिस्तान उच्च न्यायालय में जज के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की गई है।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का दावा है कि एक सरकारी एजेंसी ने इस बारे में प्रांतीय सरकार और बलोचिस्तान उच्च न्यायालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें जज मोहम्मद अली मुबीन को उच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रांतीय सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बलोचिस्तान उच्च न्यायालय के कुछ वरिष्ठ जजों ने एक कनिष्ठ जज को पदोन्नत करने पर एतराज जताया है। दूसरी ओर, सूत्रों का कहना है कि बलोचिस्तान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस फैसले से सहमत हैं। अगले कुछ दिनों में बलोचिस्तान उच्च न्यायालय मोहम्मद अली मुबीन समेत कई दूसरे जजों को न्यायमूर्ति के तौर पर नियुक्त करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। सनद रहे, उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मुनीर कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर यह आशंका जताई थी कि डॉ. महरंग बलोच और सिबगतुल्लाह शाह को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद अली मुबीन को बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में जज बनाया जा सकता है।

बलोच सॉलिडेरिटी कमेटी की नेता डॉ. महरंग बलोच को ग्वादर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक सैनिक की मौत के मामले में आतंकवाद और देशद्रोह का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

बलोच सॉलिडेरिटी कमेटी ने अपने दो नेताओं को मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को केची बेग कमालू गांव तक रैली निकाली गई।

इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। क्वेटा में शुक्रवार रात बड़ी संख्या में लोग सरयाब रोड पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बलोच नेताओं के लिए न्याय की भी मांग की।

पिछले वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित हुईं महरंग पिछले एक दशक में इस आंदोलन की सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बन गई हैं। उन्हें बलूचिस्तान की शेरनी भी कहा जाता है।

पाकिस्तान के कराची में रेंजर्स मुख्यालय पर हमले में पांच आतंकी ढेर, तीन जवानों की मौत

➲ इस्लामाबाद, (वेब वार्ता)।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में शनिवार रात सिंध रेंजर्स मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले में तीन जवानों की जान चली गई। इस दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में पांच आतंकवादी मारे गए। एक हमलावर को घायलावस्था में जीवित पकड़ लिया गया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया एवं जनसंपर्क शाखा आईएसपीआर ने इसकी पुष्टि की।

पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आईएसपीआर की विज्ञप्ति में कहा गया कि सुरक्षा बलों ने सिंध रेंजर्स मुख्यालय पर आतंकी हमले को विफल कर दिया। यह हमला प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े आतंकी संगठन जमात-उल-अहरार ने किया। आतंकवादियों ने शनिवार रात लगभग 8:30 बजे कराची के घनी आबादी वाले गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में स्थित सिंध रेंजर्स के स्थानीय मुख्यालय पर हमला किया।

सिंध के पुलिस महानिरीक्षक जावेद आलम ओधो ने देररात हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना में रेंजर्स के तीन जवान शहीद हो गए। प्रांतीय पुलिस प्रमुख ने कहा कि हमलावरों ने सबसे पहले अपनी गाड़ी परिसर के मुख्य गेट से टकरा दी। उन्होंने बताया कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडो, एंटी-टेररिस्ट फोर्स और रेंजर्स के जवानों ने तत्परता से मोर्चा संभाला।

इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से संबद्ध जमात-उल-अहरार ने ली है। यह गुट हाल के वर्षों में मुख्य रूप से खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय रहा है और आम नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाता रहा है।

एक पुलिस अधिकारी ने पहचान न उजागर करने की शर्त पर बताया कि इस हमले में कम से कम चार रेंजर्स जवान शहीद हुए हैं। अधिकारी ने कहा, पांच आतंकवादी भी मारे गए हैं और छठे आतंकवादी का शव भी मिल गया है। जिस आतंकी का शव मिला है, वह आत्मघाती हमलावर है। एक अन्य सूत्र ने दावा किया कि एक आतंकवादी को जिंदा और एक आतंकवादी को घायल हालत में भी पकड़ा गया है।

कराची में इससे पहले बड़ा आतंकवादी हमला 6 अक्टूबर 2024 को हवाई अड्डे के पास हुआ था। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और विदेशी नागरिकों सहित 11 अन्य घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। फरवरी 2023 में आतंकवादियों ने शाहराह-ए-फैसल पर कराची पुलिस कार्यालय पर हमला कर चार लोगों को मार डाला था। इस दौरान प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े तीन आतंकवादी भी मारे गए थे।

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉनफ्लिक्ट

डीआर कांगो में इबोला के मामले 1,200 के पार, सामुदायिक प्रतिरोध से जूझ रही सरकार

किंशासा, (वेब वार्ता)। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआर कांगो) में इबोला के मामलों की संख्या 1,200 के पार पहुंच गई है।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गत मई के मध्य में प्रकोप घोषित किये जाने के बाद से अब तक संक्रमण के 1,203 पुष्ट मामले सामने आये हैं तथा 321 लोगों की मौत हुई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार देर रात जारी ताजा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 148 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 419 अन्य मरीज पृथकवास में हैं अथवा अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के इबोला वायरस से फैला यह प्रकोप इतुरी, उत्तर किवु और दक्षिण किवु प्रांतों के 34 स्वास्थ्य क्षेत्रों में फैल चुका है। इतुरी इस महामारी का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इस बीमारी पर नियंत्रण के प्रयासों के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। इनमें मृत्यु के बाद जांच का सामुदायिक स्तर पर विरोध, इतुरी में सीमित उपचार क्षमता तथा संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की दर का 95 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रहना शामिल है। मंत्रालय ने कहा, "सरकार सभी को याद दिलाती है कि इबोला के खिलाफ लड़ाई हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक से अपील है कि किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना दें, स्वच्छता संबंधी उपायों का पालन करें और मृत व्यक्तियों के शवों को हाथ न लगाएं।"

4 दिन में तीसरी बार भूकंप से हिला जापान, इवाते में 6.1 की तीव्रता से कांपी धरती; दहशत में लोग

➲ टोक्यो, (वेब वार्ता)।

जापान में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार सुबह एक बार फिर देश का उत्तरी हिस्सा शक्तिशाली भूकंप के झटकों से दहल उठा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है।

पिछले महज चार दिनों के भीतर जापान में आया यह तीसरा बड़ा और शक्तिशाली भूकंप है, जिसने वैज्ञानिकों और सरकार की चिंताओं को चरम पर पहुंचा दिया है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस ताजा भूकंप के बाद फिलहाल कोई सुनामी अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

रविवार सुबह इवाते प्रांत में आया भूकंप जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) के अनुसार, रविवार को आए इस भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत का तटीय इलाका था। स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 5:21 बजे जब लोग गहरी नींद में थे, तभी धरती तेज झटकों के साथ कांपने लगी। भूकंप का केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

रिपोर्टों के अनुसार, आमोरी प्रांत के हाचिनोहे शहर में भूकंप की तीव्रता काफी अधिक महसूस की गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में किसी के हताहत होने या जान-माल के बड़े नुकसान की खबर नहीं है।

जापान में पिछले 96 घंटों के दौरान भूकंपों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसने 2011 की भयावह यादें ताजा कर दी हैं।

गुरुवार (25 जून) को उत्तरी जापान के इवाते प्रांत में 7.2 तीव्रता का महाविनाशकारी भूकंप आया था।

वेनेजुएला में भूकंप से तबाही बढ़ी,हताहतों की संख्या 1,430 पहुंचीं

➲ काराकास, (वेब वार्ता)।

वेनेजुएला में हाल ही में आए दो शक्तिशाली भूकंप के झटकों से लाखों लोग संकट में हैं। मृतकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्ज ने शनिवार को देश के भूकंप प्रभावित उत्तर-मध्य इलाके के हालात का ताजा विवरण दुनिया के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि 24 जून को आए भूकंप से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 1,430 हो गई है और 3,238 लोग घायल हुए हैं।

वेनेज़ुएला के स्पेनिश भाषा के समाचार पत्र द नेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, रोड्रिग्ज ने देश के नाम संबोधन में कहा कि इस त्रासदी में 3,142 परिवार बेघर हो गए हैं और भूकंप से प्रभावित सात राज्यों में बनाए गए अस्थाई शेल्टर में उनकी देखभाल की जा रही है। उन्होंने कहा, हम अपने 1,430 साथी नागरिकों की मौत की जानकारी दे रहे हैं। हम इन वेनेजुएला के नागरिकों के परिवारों और उनके चाहने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

इसके अलावा कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि 10 और देशों की बचाव टीमें जल्द ही राहत अभियान में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि ला ग्वाइरा में सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता कार्यों के लिए 14 हजार सैनिकों और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। भूकंप के केंद्र मोरोन और ला ग्वाइरा के कुछ हिस्सों में अब भी बिजली आपूर्ति बाधित है।

बताया गया है कि वेनेजुएला के तटीय शहर ला ग्वाइरा में कम से कम 100 आवासीय बहुमंजिला इमारतें पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों का कहना है कि भारी मशीनों की कमी और राहत कार्यों की धीमी गति के कारण बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है।

सरकार का कहना है कि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं या मलबे में फंसे हो सकते हैं। वहीं, विपक्ष की एक वेबसाइट पर 54 हजार से अधिक लोगों को लापता होने का दावा किया गया है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि 7.2 और 7.5 तीव्रता के इन दोनों भूकंपों से मरने वालों की संख्या 10 हजार से अधिक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह पिछले एक शताब्दी में लैटिन अमेरिका की सबसे घातक भूकंप त्रासदी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस आपदा से करीब 70 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। संगठन ने प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान का अनुमान लगभग 6.7 अरब डॉलर लगाया है। वेनेजुएला सरकार ने बताया कि शनिवार तक विभिन्न देशों से 1,600 बचावकर्मी राहत और खोज अभियान में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं, अमेरिका से राहत सामग्री लेकर पहली सहायता उड़ानें भी काराकास पहुंच गई हैं।

दो मोटरसाइकिलें भिड़ीं, एक की मौत ,दो घायल

बलरामपुर (वेब वार्ता)। जनपद में तुलसीपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर -बलरामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार दोपहर लगभग 3:30 बजे ग्राम निबोरिया स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मिली जानकारी के मुताबिक थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र निवासी 35 वर्षीय शमशाद और 20 वर्षीय इकबाल पुत्र जाहिद चौधरी पल्सर मोटरसाइकिल से तुलसीपुर की ओर आ रहे थे। दूसरी तरफ से ग्राम लाला जोत निवासी हरिराम पुत्र कुलदीप मौर्य अपनी डीलक्स मोटरसाइकिल से जा रहे थे। ग्राम निबोरिया के पास दोनों में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पल्सर सवार इकबाल की बाइक अनियंत्रित होकर पहले बिजली के पोल से टकराई और फिर वहां खड़े एक ट्रक के नीचे जा घुसी। हादसे में इकबाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पल्सर सवार शमशाद और दूसरी बाइक के चालक हरिराम को स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से एंबुलेंस द्वारा तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। दोनों की हालत गंभीर बनी है।

उपनिरीक्षक अरविंद सरोज ने बताया कि मृतक इकबाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ट्रक की टक्कर से युवक घायल

हाथरस, (वेब वार्ता)। सादाबाद के विनोबा नगर चौराहे पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दिया। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घायल युवक की पहचान सलेमपुर निवासी अमित कुमार पुत्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अमित कुमार रात के समय सड़क पार कर रहा था, तभी हाथरस की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और तत्काल एंबुलेंस तथा पुलिस को सूचना दी गई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के दौरान युवक की हालत गंभीर देख उसे बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल युवक से पूछताछ कर उसकी पहचान सुनिश्चित की और उसके परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए, जहां युवक की गंभीर स्थिति को देखकर परिवार के लोगों में चिंता का माहौल बन गया। पुलिस का कहना है कि फरार ट्रक और उसके चालक की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि वाहन की पहचान कर आरोपी चालक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

गंडक नदी में नहाने के दौरान युवक की डूबने से मौत

देवरिया, (वेब वार्ता)। लार थाना क्षेत्र के महरौना स्थित गंडक नदी में रविवार को नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है।

थानेदार लार राकेश सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान मायापुर निवासी सलील साहनी (24) के रूप में हुआ हैं। परिवार से पता चला है कि युवक गंडक नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। बाद में युवक को नदी से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

घटना की सूचना पर लार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, युवक की असामयिक मौत से परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। ग्रामीणों ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और नदी किनारे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने की मांग की।

करंट लगने से महिला की मौत

कानपुर, (वेब वार्ता)। ककवन थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार को घर में बिजली के बोर्ड से पंखे का प्लग निकालते समय करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

मृतका की पहचान लोधनपुरवा गांव निवासी फूलमती (60) के रूप में हुई। परिवार के लोगों ने बताया कि फूलमती आज घर में बिजली के बोर्ड से पंखे का प्लग निकाल रही थीं। इसी दौरान अचानक उन्हें तेज करंट लग गया, जिससे वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ीं।

परिजन आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतका अपने पीछे एक बेटा और दो बेटियां छोड़ गई हैं। तीनों बच्चों का विवाह हो चुका है।

सूचना पर ककवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया और परिजनों से जानकारी जुटाई।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला करंट लगने से हुई दुर्घटनावश मौत का प्रतीत होता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा जांच के बाद अस्पतालों पर नजर, मांगा गया जवाब

कानपुर देहात, (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी केंद्रों की सुरक्षा जांच के बाद अब प्रशासन ने अगले चरण की कार्रवाई तेज कर दी है। निरीक्षण के दौरान जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर कमियां मिली थीं, उनसे जवाब तलब किया गया है और अधिकारियों ने अनुपालन रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पिछले दिनों जिले के कई निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान भवन सुरक्षा, आपातकालीन निकास व्यवस्था, बेसमेंट उपयोग, अग्निशमन प्रबंधन और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है, उनसे तय समय के भीतर स्पष्टीकरण और

अखिलेश जी, अयोध्या को रामभक्तों ने संवारा

आप पश्चाताप कर रामलला के दर्शन करिएः मुख्यमंत्री योगी

» मुख्यमंत्री योगी ने हाथरस, सिकंदराराऊ व सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में 548 करोड़ रुपये की लागत से 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया

» सपा अध्यक्ष सच में धार्मिक हैं तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलें: मुख्यमंत्री योगी

» 2017 से पहले मंदिरों का पैसा कब्रिस्तानों में जाता था, हमने आस्था के केंद्रों के विकास में लगाया: मुख्यमंत्री योगी

» मोहर्रम पर 12 हजार जुलूस निकले, लेकिन कहीं भी दंगा, उपद्रव या कर्फ्यू नहीं

» मुख्यमंत्री योगी ने नन्ही बच्ची को गोद में लेकर चम्मच से पिलाया दूध, किया दुलार

➲ हाथरस, (वेब वार्ता)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाने की बात करने वालों को पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया, कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों पर रोक लगाई और कांवड़ यात्रा तक प्रतिबंधित कर दी, वह आज अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाने की बात कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हाथरस में हाथरस, सिकंदराराऊ व सादाबाद तीन विधानसभा क्षेत्रों में 548 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। वहीं लाभार्थियों को आवास की चाभी, स्मार्ट फोन, युवा उद्यमी योजना के तहत चेक वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टॉल के पास एक नन्ही बच्ची को चम्मच से दूध पिलाया, गोद में लेकर दुलार किया।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा अखिलेश यादव का बयान पढ़कर आश्चर्य हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, अरे, आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे। पहले अपना इतिहास देखिए। आपकी ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने रामभक्तों पर गोलियां चलाई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या त्रेता युग की स्मृतियों को साकार करती दिखाई दे रही है। रामभक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी को भी अयोध्या की याद आने लगी है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने थानों और जेलों में होने वाले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम तक बंद करा दिए थे। कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब हाथरस में 22 से अधिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराया गया है, लेकिन यह कार्य समाजवादी सरकार में कभी संभव नहीं था। तब यही पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्रीवाल बनाने में खर्च होता था। हमने वही पैसा मंदिरों की ओर डायवर्ट किया है। कब्रिस्तानों की नहीं, मंदिरों की आवश्यकता है क्योंकि मंदिर हमारी आस्था के केंद्र हैं।

रामलला के दर्शन कर लो, शायद सद्बुद्धि आ जाए

मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए कहा कि वे अयोध्या की चिंता छोड़ दें क्योंकि अयोध्या अपनी पहचान के लिए किसी की मोहताज नहीं है। अखिलेश जी, अयोध्या को रामभक्तों ने सजाया और संवारा है। आप उसकी चिंता मत करिए। पश्चाताप कर एक बार रामलला के दर्शन कर लीजिए, शायद सद्बुद्धि आ जाए। सपा वास्तव में धार्मिक आस्था का सम्मान करना चाहती है तो उसे खुलकर मथुरा-वृंदावन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला था, उसी प्रकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी अभियान चलाने की बात समाजवादी पार्टी को खुलकर करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि आने वाले श्रद्धालुओं को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि उसका पूरा एजेंडा केवल तुष्टिकरण की राजनीति तक सीमित है।

देश को पोलियो मुक्त रखने के लिए हर बच्चे को खुराक पिलाना जरूरी : डॉ. शलभ मणि

➲ देवरिया, (वेब वार्ता)।

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (एमसीएच विंग) से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार गुप्ता एवं मेडिकल कॉलेज की प्राचार्या डॉ. रजनी पटेल के साथ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की।

इस अवसर पर सदर विधायक डॉ. शलभ मणि ने कहा कि देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए प्रत्येक बच्चे तक पोलियो रोधी दवा पिलाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम समय पर दी जाने वाली दो बूंद जिंदगी की खुराक है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे दूर-दराज के गांवों और हर घर तक पहुंच सुनिश्चित करें, ताकि शून्य से पांच वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रह जाए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में इस अभियान के तहत पांच वर्ष तक के 5.68 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों पर पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा बस स्टैंड, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांजिट टीमों की भी तैनाती की गई है, ताकि यात्रा कर रहे बच्चों को भी पोलियो की दवा दी जा सके।

सीएमओ ने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर अवश्य ले जाएं और उन्हें पोलियो रोधी खुराक दिलाएं। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. एस.के. सिन्हा, डिप्टी सीएमओ डॉ. अश्वनी पाण्डेय, डॉ. कार्तिक पाण्डेय, डिप्टी डीआईओ डॉ. विपिन रंजन, डीसीपीएम राजेश गुप्ता, जिला मलेरिया अधिकारी सुधाकर मणि, तथा सहयोगी संस्थाओं जेएसआई, डब्ल्यूएचओ एवं यूएनडीपी के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अभियान के शुभारंभ के बाद सीएमओ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बरहज क्षेत्र में स्थापित पोलियो बूथ का निरीक्षण किया। उन्होंने दवाओं के रखरखाव, कोल्ड चेन व्यवस्था और बच्चों को पिलाई जा रही खुराक की जानकारी ली तथा अभियान को पूरी सतर्कता और गुणवत्ता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए।

वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनी शिवानी

➲ हाथरस, (वेब वार्ता)।

सादाबाद थाना क्षेत्र के गांव बरामई की रहने वाली शिवानी चौधरी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन गई है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल है। शुभकामनाएं देने वालों का उनके घर पर तांता लगा हुआ है। ग्राम प्रधान शशि मुकेश चौधरी ने शिवानी का स्वागत करते हुए नागरिक अभिनंदन किया।

शिवानी के पिता खरग सिंह पोस्टमैन हैं। बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहीं शिवानी ने अनुशासित दिनचर्या, निरंतर मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण के दम पर यह सफलता हासिल की।

बरामई गांव के रहने वाले खरग सिंह एक पोस्टमैन है जिनके दो बेटे और एक बेटी है। शिवानी की माता राजेश देवी गृहिणी हैं। बड़े भाई संतोष कुमार इंजीनियर हैं जबकि दूसरे भाई अतुल मैकेनिकल इंजीनियर हैं। परिवार ने बेटी की सफलता पर गर्व जताते हुए इसे पूरे क्षेत्र की उपलब्धि बताया।

शिवानी ने कहा, भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनना मेरा बचपन का सपना था। पहले ही प्रयास में सफलता मिलना मेरे लिए गर्व के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुओं और परिवार के सहयोग को देती हूं।

यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और पूरी ईमानदारी से मेहनत की जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।

पिता खरग सिंह ने बेटी की सफलता का श्रेय उसकी कड़ी मेहनत और परिवार के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया।

उन्होंने बताया कि शिवानी बचपन से ही देशसेवा का सपना देखती थीं और उसी लक्ष्य को सामने रखकर लगातार तैयारी करती रहीं। गांव में लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया।

ग्रामीणों ने कहा कि शिवानी की सफलता से क्षेत्र की बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की नई प्रेरणा मिलेगी।

वहीं सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि बरामई की बेटी शिवानी चौधरी ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर पूरे सादाबाद क्षेत्र का मान बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।

शिवानी ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन से साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं।

देवरिया मेडिकल कॉलेज में डेढ़ वर्षीय बालक का जटिल ऑपरेशन सफल, विशेषज्ञों ने बचाई जान

देवरिया, (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रविवार को डेढ़ वर्षीय बालक का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गंभीर स्थिति में भर्ती किए गए बालक का समय रहते ऑपरेशन कर चिकित्सकों ने उसकी जान बचाई है।

प्राचार्या डॉ रजनी पटेल ने बताया कि महाविद्यालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भर्ती बालक लेफ्ट टेस्टिकुलर टॉर्शन से पीड़ित था। जांच के दौरान चिकित्सकों ने पाया कि बाएं अंडकोष में रक्त संचार पूरी तरह बंद हो चुका था। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ टीम ने लेफ्ट ऑर्किडेक्टॉमी की, जबकि भविष्य में दाएं अंडकोष को सुरक्षित रखने के लिए राइट ऑर्किडोपेक्सी सफलतापूर्वक की गई।

उन्होंने बताया कि इस जटिल शल्य चिकित्सा का नेतृत्व डॉ. वैभव शर्मा (एमसीएच यूरोलॉजी) एवं डॉ. मानवेन्द्र (सहायक प्रोफेसर) ने सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार के मार्गदर्शन में किया। वहीं एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष डॉ. धीरज और सीनियर रेजिडेंट डॉ. कृष्णा ने सफलतापूर्वक निभाई। ऑपरेशन के बाद बालक सुरक्षित रूप से एनेस्थीसिया से बाहर आ गया और उसकी स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है।

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने किया पुस्तक 'उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम और इटावा' का विमोचन

➲ औरैया, (वेब वार्ता)।

उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने रविवार को पूर्व डीआईजी हरीश कुमार द्वारा लिखित पुस्तक 'उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम और इटावा' का विमोचन किया। कार्यक्रम शहर के जालौन रोड स्थित रंग महल रिसॉर्ट में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया ने की, जबकि संचालन डॉ. कुश चतुर्वेदी एवं उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार अग्निहोत्री ने संयुक्त रूप से किया। पूर्व मंत्री लाखन सिंह राजपूत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 135वें एपिसोड को एलईडी स्क्रीन पर सुनने एवं देखने के साथ हुआ। इसके उपरांत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रधानाचार्या गीता चतुर्वेदी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की।

मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का माल्यार्पण, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया।

पुस्तक विमोचन के बाद अपने संबोधन में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि यह पुस्तक लेखक की गहन मेहनत और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति है, जो नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जोड़ने का कार्य करेगी।

विशिष्ट अतिथि लाखन सिंह राजपूत ने पूर्व डीआईजी हरीश कुमार को पुस्तक विमोचन की बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की।

मेगा स्वास्थ्य शिविर में दो हजार से अधिक ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

➲ बलिया, (वेब वार्ता)।

पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 'जननायक की स्मृति में जनसेवा का संकल्प' अभियान के तहत रविवार को गड़हांचल के पिपरा में आयोजित विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में भीषण गर्मी के बावजूद हजारों लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। भारी भीड़ के चलते देर शाम तक चिकित्सक डटे रहे।

शिविर का आयोजन स्व. चंद्रशेखर की पुत्रवधू एवं राज्यसभा सांसद नीरज शेखर की पत्नी डॉ. सुषमा शेखर के प्रयासों से किया गया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 2300 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क परामर्श एवं दवाएं उपलब्ध कराईं। इसके पहले शिविर का उद्घाटन डॉ. सुषमा शेखर ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शिविर में सबसे पहले कुल 2361 लोगों ने पंजीकरण कराया। इसके बाद इन सभी मरीजों की बीमारियों के अनुसार वर्गीकरण किया गया।

हड्डी रोग, बाल रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, सामान्य चिकित्सा तथा नेत्र रोग सहित विभिन्न विभागों के अलग-अलग काउंटर बनाए गए थे। यहां रक्त जांच, नेत्र जांच, हृदय जांच समेत अन्य आवश्यक जांचें भी निःशुल्क की गईं। जरूरतमंद मरीजों को चश्मों का भी वितरण किया गया तथा चिकित्सकीय सलाह के आधार पर मोतियाबिंद सहित अन्य नेत्र ऑपरेशन के लिए पंजीकरण भी किया गया। सबसे अधिक हड्डी से संबंधित काउन्टर पर भीड़ देखी गई। आई सर्जन देर शाम तक मरीजों का परीक्षण करते रहे। इसके पूर्व अभय नारायण सिंह, पूर्व प्रधान शैलेंद्र सिंह, अनिल सिंह प्रधान, चौरा के प्रधान प्रतिनिधि अनिल सिंह, मंटू पंडित, ओमप्रकाश वर्मा, विश्वकर्मा शर्मा, मण्डल उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह, मुन्ना सिंह प्रधान पिपरा, राजू सिंह प्रधान कथरिया, जितेंद्र राय व रियाजुद्दीन राजू आदि ने डॉ. सुषमा शेखर का स्वागत किया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए डॉ. सुषमा शेखर ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना समय की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से ये स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फेफना विधानसभा क्षेत्र में हर नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना मेरा लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि चन्द्रशेखर जी के विचारों से प्रेरित होकर यह उनके जन्म शताब्दी वर्ष में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जनसेवा ही उनका धर्म है तथा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सेवा भाव को आगे बढ़ाना ही उनका उद्देश्य है।

रेलवे ने भेजे 9 टन आलूबुखारे कश्मीर से चेन्नई और कोलकाता

जम्मू, (वेब वार्ता)। कश्मीर के मौसमी फलों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन ने पिछले पांच दिन में पार्सल सेवा के जरिए नौ टन से ज्यादा ताजे आलूबुखारे चेन्नई और कोलकाता भेजे हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि चेरी और लीची की सफल लोडिंग के बाद, आलूबुखारे की यह खेप जम्मू-कश्मीर से देश के अलग-अलग हिस्सों में ताजे फल पहुंचाने की कड़ी में अगला अहम कदम है।

उन्होंने बताया कि जम्मू डिवीजन ने शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से चेन्नई के लिए ताजे आलूबुखारे के 284 पैकेट (तीन टन) भेजे। इसके अलावा 22 से 25 जून के बीच जम्मू तवी से कोलकाता के लिए आलूबुखारे के लगभग 587 पैकेट (6.1 टन) भेजे गए।

जम्मू के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने कहा कि कटरा और जम्मू तवी से आलूबुखारे की सफल लोडिंग विभाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, ''चेरी और लीची के बाद, आलूबुखारे की लोडिंग यह साबित करती है कि हमारी कोशिशें कश्मीर के किसानों को सीधे बड़े बाजारों से जोड़ रही हैं। रेलवे तेजी से बुकिंग और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है।''

उन्होंने कहा कि मकसद यह पक्का करना है कि कश्मीर का हर मौसमी फल देश के हर कोने तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और बागवानों को रेलवे की पार्सल सेवा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि पार्सल सेवा के जरिए जम्मू डिवीजन कश्मीर के बागवानों को सीधे राष्ट्रीय बाजार से जोड़ रहा है।

उन्होंने कहा, ''चेरी और लीची के बाद लगातार आलूबुखारे की लोडिंग यह दिखाती है कि रेलवे ताजे और जल्दी खराब होने वाले फलों के परिवहन के लिए सबसे भरोसेमंद और किफायती विकल्प के तौर पर उभर रहा है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं और ग्राहकों तक ताजे फल समय पर पहुँच रहे हैं।''

हिमाचल सरकार बकाया कृषि ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज का बोझ उठाएगी

शिमला, (वेब वार्ता)। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य बजट की एक अहम घोषणा को पूरा करते हुए एकमुश्त निपटान नीति के तहत 'कृषि ऋण ब्याज सहायता योजना' शुरू करने का फैसला किया है।

यह योजना उन किसानों को मदद देगी जिनकी कृषि भूमि ऋण न चुका पाने के कारण नीलाम होने के खतरे में है। शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, किसानों के लिए शुरू की गई इस पहल के तहत, सरकार प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर बकाया ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्सा खुद वहन करेगी।

इस योजना से राज्य भर में लगभग 6,356 किसानों को फायदा होने की उम्मीद है और इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

यह योजना 'हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' और 'कांगड़ा सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' के माध्यम से लागू की जाएगी। संबंधित शाखाएं ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र कर्जदारों की पहचान करेंगी और उनकी सूची तैयार करेंगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनका कल्याण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कई किसान मुश्किल हालात के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इसलिए सरकार ने पात्र लाभार्थियों को एकमुश्त मदद देने का फैसला किया है।

इस योजना में वे किसान शामिल होंगे जिनके कृषि ऋण की समय-सीमा खत्म हो चुकी है और जिनकी जमीन वित्तीय संस्थानों द्वारा नीलाम किए जाने के खतरे में है। बकाया ब्याज का आधा बोझ उठाकर, सरकार का मकसद ऋण को विनियमित करने में मदद करना, आर्थिक तनाव कम करना और किसानों को अपनी जमीन खोने के डर के बिना खेती जारी रखने में सक्षम बनाना है।

उन्होंने संबंधित विभागों और वित्तीय संस्थानों को योजना को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया ताकि जरूरतमंद किसानों को समय पर मदद मिल सके।

वाणिज्य मंत्रालय विशेष आर्थिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर हितधारकों से करेगा बैठक

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। वाणिज्य मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के मकसद से 30 जून को हितधारकों की बैठक बुलाई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि बैठक में निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और एसईजेड सुधारों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।

बैठक में एसईजेड से घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) को दी जाने वाली सेवाओं के लिए भारतीय मुद्रा में भुगतान की व्यवस्था, डीटीए के लिए निर्यात से असंबद्ध जॉब वर्क की अनुमति, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा, मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों में सुधार तथा कारोबार सुगमता को और बेहतर बनाने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

जन धन, आधार और UPI का कमाल, 2 करोड़ से बढ़कर 24,162 करोड़ हुआ ट्रांजैक्शन

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

10 साल में UPI ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के मामले में एक नया इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, आधार और मोबाइल (जेएएम) क्रांति ने पूरा देश बदल दिया है।

एक आधिकारिक फैक्टशीट में शनिवार को कहा गया कि 10 वर्ष पहले एक साधारण डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आज भारत में रोजमर्रा के डिजिटल कारोबार की रीढ़ बन चुकी है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए केवल 2 करोड़ लेनदेन (ट्रांजैक्शन) हुए थे, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई।

बयान में कहा गया है कि जन धन, आधार और मोबाइल ने भारत में वित्तीय समावेशन और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। इस पहल के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया और उन्हें सरकारी सेवाओं तक आसान और पारदर्शी पहुंच मिली।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से देशभर में बैंकिंग सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ। मार्च 2015 में जन धन खातों की संख्या 14.72 करोड़ थी, जो फरवरी 2026 तक बढ़कर 57.78 करोड़ हो गई। इसी अवधि में इन खातों में जमा राशि 15,670 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। फैक्टशीट के अनुसार, आधार ने देश में सुरक्षित और त्वरित डिजिटल पहचान उपलब्ध कराई। वर्ष 2010-11 में आधार नामांकन केवल

0.42 करोड़ था, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 144 करोड़ से अधिक हो गया। इससे डिजिटल प्रमाणीकरण पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और आसान बना है।

मोबाइल कनेक्टिविटी ने जैम ट्रिनिटी को और मजबूत बनाया तथा देश भर में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाई। मार्च 2026 तक भारत के 85.5 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक स्मार्टफोन था, जबकि 109 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे। इन तीनों पहलों ने मिलकर डिजिटल इंडिया के समावेशी शासन मॉडल की मजबूत नींव तैयार की। जून 2026 तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि 176 करोड़ लाभार्थियों के खातों में सीधे भेजी जा चुकी है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचा है।

डिजिलॉकर ने कागजी दस्तावेजों की जगह सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। मार्च 2026 तक इस प्लेटफॉर्म पर 70.69 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं, जबकि 850 करोड़ से अधिक डिजिटल दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। इससे दस्तावेजों का सत्यापन तेज, कागजरहित और अधिक भरोसेमंद बना है।

11 लाख से ज्यादा MSMEs को मिला बाजार

बयान में कहा गया है कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। जून 2026 तक जेम पर कुल 18.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार मूल्य (जीएमवी) दर्ज किया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार शामिल है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए 11 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सरकारी बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिला है।

औद्योगिक आंकड़ों, मानसून की प्रगति से तय होगी बाजार की दिशा

➲ मुंबई, (वेब वार्ता)।

घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर वैश्विक कारकों के साथ घरेलू स्तर पर जारी होने वाले औद्योगिक आंकड़ों और मानसून की प्रगति पर रहेगी।अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते की दिशा में प्रगति का सीधा असर शेयर बाजार पर दिखेगा। साथ ही मानसून की प्रगति भी अहम कारक होगा। मानसून 10 दिन तक अटकने के बाद पश्चिमी भारत में तो आगे बढ़ा है, लेकिन पूर्वी भारत में आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे निवेश धारणा पर नकारात्मक असर हो सकता है।

अगले सप्ताह कई महत्वपूर्ण औद्योगिक आंकड़े जारी होने हैं। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े, पीएमआई के आंकड़े और वाहन कंपनियों के बिक्री के आंकड़े भी निवेशकों के रुख को प्रभावित करेंगे।

बीते सप्ताह बीएसई का सेंसेक्स 297.57 अंक (0.39 प्रतिशत) चढ़कर 77,100.47 अंक पर पहुंच गया। इसमें दो दिन तेजी और दो दिन गिरावट देखी गई।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 42.90 अंक यानी 0.18 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त के साथ 24,056 अंक पर बंद हुआ।

वृहत बाजार में निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.83 प्रतिशत लुढ़क गया जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.03 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ।

सेंसेक्स की 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में साप्ताहिक तेजी और अन्य 15 में गिरावट रही। पश्चिम एशिया शांति स्थापित होने से विमान सेवा कंपनी इंडिगो का शेयर सबसे अधिक 8.48 प्रतिशत चढ़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.48 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 3.05 फीसदी, मारुति सुजुकी में 2.60, कोटक महिंद्रा बैंक में 2.53 और एचडीएफसी बैंक में 2.06 फीसदी की तेजी रही।

बजाज फाइनेंस का शेयर 1.93 प्रतिशत, टेक महिंद्रा का 1.83, एक्सिस बैंक का 1.38, सनफार्मा का 1.36 और अल्ट्राटेक सीमेंट का 1.08 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। भारतीय स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेंट और एलएंडटी के शेयर भी हरे निशान में रहे।

टाटा स्टील में सबसे अधिक 5.13 फीसदी की गिरावट रही। बीईएल का शेयर 4.76 प्रतिशत, एनटीपीसी का 3.72, इटरनल का 3.39, एशियन पेंट्स का 3.22 और भारती एयरटेल का 3.06 और टाइटन का 3.02 प्रतिशत टूट गया।

पावरग्रिड में 2.89 फीसदी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 2.51, अडानी पोर्ट्स का 2.11, टीसीएस का 1.45, आईटीसी का 1.14, हिंदुस्तान यूनीलिवर का 1.03 प्रतिशत और इंफोसिस का 0.99 प्रतिशत फिसल गया

'मेड इन इंडिया' सिर्फ लेबल नहीं, बल्कि गुणवत्ता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी : गोयल

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 'मेड इन इंडिया' केवल किसी उत्पाद पर अंकित लेबल नहीं, बल्कि यह गुणवत्ता के प्रति भारत की प्रतिष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता केवल कंपनियों के प्रदर्शन का पैमाना नहीं, बल्कि देश के प्रति एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है।

गोयल ने लंदन में 27 जून को आयोजित एक कारोबारी सत्र में तमिलनाडु के अंबूर स्थित फ्लोरेंस शू कंपनी के संस्थापक अकील अहमद पनारूना की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय उद्यमी विश्वस्तरीय विनिर्माण के जरिये 'ब्रांड इंडिया' की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि एक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक ने काहिरा हवाई अड्डे पर लक्जरी ब्रांड ह्यूगो बॉस का एक जूता देखा। जूते पर लगे लेबल की जांच करने पर उस पर 'मेड इन इंडिया' अंकित मिला। यह जूता अंबूर स्थित फ्लोरेंस शू कंपनी में तैयार किया गया था।

गोयल ने कहा, "जब किसी उत्पाद पर 'मेड इन इंडिया' लिखा होता है, तो वह

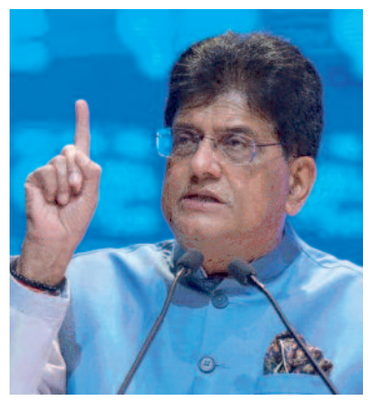

केवल एक कंपनी का नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है।" उन्होंने कहा कि अकील जैसे उद्यमियों के लिए गुणवत्ता केवल कारोबारी मानक नहीं, बल्कि राष्ट्र के सम्मान और भरोसे से जुड़ी जिम्मेदारी है।

सोशल मीडिया पर साझा संदेश में मंत्री ने कहा कि पनारूना ने भारतीय कारीगरी को दुनिया के प्रतिष्ठित ब्रांड तक पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया है। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने और 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' जैसी पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है।

उप्र रेरा का वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ सख्त रुख

लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर (उप्र), (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले कुछ रियल एस्टेट प्रमोटरों के खिलाफ गंभीर रुख अपनाया है।

उप्र-रेरा ने ऐसे 76 प्रोजेक्ट चिन्हित किए हैं, जिनके प्रमोटरों ने अभी तक अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट यूपी-रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की है।

एक बयान के मुताबिक रियल एस्टेट प्रमोटरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे हर वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद अपने प्रोजेक्ट खातों का ऑडिट कराएं और छह महीने के भीतर वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट उप्र-रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि उप्र-रेरा परियोजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन कर सके तथा आम जनता और संबंधित परियोजनाओं के आवंटियों को भी सही जानकारी उपलब्ध हो सके।

वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर संबंधित वर्ष के लिए 25,000 रुपये की विलंब शुल्क देना होगा । वहीं, रेरा अधिनियम की धारा-4 और संबंधित नियमों एवं विनियमों के उल्लंघन पर परियोजना की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

उप्र-रेरा के नियमों के अनुसार परियोजना खातों का वित्तीय ऑडिट प्रमोटर द्वारा नियुक्त बाहरी ऑडिटर से कराया जाना आवश्यक है। ऑडिटर एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए और वह प्रमोटर की कंपनी, समूह या उससे जुड़ी किसी संस्था का ऑडिटर नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य परियोजनाओं की वित्तीय जानकारी में पारदर्शिता, स्वतंत्र जांच और सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।

बयान के मुताबिक परियोजनाओं की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट यूपी-रेरा की वेबसाइट पर दाखिल नहीं करना गंभीर लापरवाही है। यह रेरा अधिनियम के उन प्रावधानों के विपरीत है, जिनका उद्देश्य प्रमोटरों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

उप्र-रेरा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित प्रमोटरों को निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर निर्धारित विलंब शुल्क के साथ वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अपलोड करें। ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण द्वारा परियोजना की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संबंध में सभी उल्लंघनकर्ता प्रमोटरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

उप्र-रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा, 'वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा करना प्रत्येक प्रमोटर की रेरा के तहत मूल जिम्मेदारी है।

संकट के हर दौर में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां बनीं ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

भारत ने जब-जब किसी बड़े संकट का सामना किया है हर बार देश की सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे 2015 की विनाशकारी बाढ़ हो, कोविड-19 महामारी हो या फिर वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का संकट उत्पन्न करने वाला पश्चिम एशिया का हालिया संघर्ष।

विश्लेषकों और उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि हर राष्ट्रीय आपातकाल ने इस बात को और मजबूत किया है कि सरकारें देश की ऊर्जा जीवनरेखा को नियंत्रित करने वाली इन कंपनियों पर से अपनी पकड़ ढीली करने में क्यों कतराती रही हैं।

दशकों से भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की अक्सर कम मुनाफे, ईंधन मूल्य निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप और बड़े परिचालन के लिए आलोचना की जाती रही है। इन्हें दो बार निजीकरण के दायरे में भी लाया गया था। वर्ष 2002 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को बेचने की योजना ने गति पकड़ी, जिसे उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने रोक दिया। इसके बाद 2020 में फिर से यह प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन पर्याप्त बोलियां न मिलने के कारण इसे छोड़ दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि जब 2015 में अभूतपूर्व बाढ़ ने चेन्नई को जलमग्न कर दिया था, तब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), बीपीसीएल और एचपीसीएल ने वैकल्पिक मार्गों से ईंधन पहुंचाने, डूबे हुए डिपो को बहाल करने और आपातकालीन सेवाओं को आपूर्ति जारी रखने के लिए दिन-रात काम किया।

इसी तरह, कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद इन कंपनियों ने लगभग बिना किसी बाधा के काम किया।

उन्होंने बताया कि सख्त आवाजाही प्रतिबंधों के बीच भी ईंधन स्टेशन खुले रहे, रिफाइनरियां न्यूनतम कर्मचारियों के साथ चलती रहीं, करोड़ों घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए गए और राहत एवं चिकित्सा उड़ानों के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) की आपूर्ति बनाए रखी गई।

पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष ने एक बार फिर इन कंपनियों के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया है।

ईरान युद्ध के कारण जब कच्चे तेल के व्यापार मार्ग प्रभावित हुए और होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ीं, तो भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने तेजी से अपने परिचालन को व्यवस्थित किया।

उन्होंने पेट्रोरसायन से ध्यान हटाकर एलपीजी उत्पादन बढ़ाया, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से कच्चे तेल की खरीद में विविधता लेकर आईं और स्थानीय स्तर पर किल्लत से बचने के लिए देश भर में ईंधन की आपूर्ति का समन्वय किया।

एक उद्योग अधिकारी ने कहा, 'इसका परिणाम यह हुआ कि देश के किसी भी कोने में ईंधन की कमी नहीं हुई। पड़ोस सहित कई देशों के विपरीत, भारत में ईंधन की कोई सीमित आपूर्ति देखने को नहीं मिली।'

इन कंपनियों ने यह सब वैश्विक तेल कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी का न्यूनतम बोझ उपभोक्ताओं पर डालकर किया। तीन सरकारी कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक के उछाल को खुद झेला। इसके बाद उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7.50 रुपये प्रति लीटर, एलपीजी दरों में 89 रुपये प्रति सिलेंडर और सीएनजी में छह रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की, जो दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हुई बढ़ोतरी की तुलना में बेहद कम थी।

विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच सभी तेल-तिलहन कीमतों में मामूली सुधार

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दाम मजबूत होने के कारण बीते सप्ताह देश के तेल-तिलहन बाजारों में सभी खाद्य तेल-तिलहनों के दाम में मामूली सुधार रहा। इसके चलते सरसों, सोयाबीन एवं मूंगफली तेल-तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन तथा बिनौला तेल के दाम मजबूत बंद हुए।

बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि विदेशों में बाजार मजबूत हुए हैं पर देश के हाजिर कारोबार में मांग कमजोर रहने से कारोबारी गतिविधियां धीमी हैं। इस कारण विदेशों में जिस तरह दाम बढ़े हैं, उसकी रफ्तार देश के बाजार में धीमी है जिससे तेल-तिलहन कीमतों में मामूली सुधार नजर आया।

सूत्रों ने कहा कि देश के बाजारों में ऊंचे दाम की वजह से सरसों की मांग बेहद कमजोर है। कारोबारी सरसों का दाम बढ़ाकर बोल रहे हैं जिससे सरसों तेल-तिलहन में सुधार दिख रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों को पिछले कुछ वर्षों बाद पहली बार सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अच्छे दाम मिले हैं। वे ऊंची कीमत का स्वाद चख चुके हैं और प्लांट वालों द्वारा दाम घटा-बढ़ाकर बाजार प्रभावित करने के असर से बेअसर हैं। किसान अच्छे दाम पर ही सोयाबीन बेचने के पक्ष में नजर आते हैं जिससे बीते सप्ताह सोयाबीन तिलहन के दाम में मजबूती दिखी।

विदेशों में बाजार मजबूत होने से सोयाबीन तेल कीमतों में भी बीते सप्ताह सुधार आया। लेकिन यह भी हकीकत है कि आयातक अब भी आयात लागत से नीचे दाम पर सोयाबीन, पाम-पामोलीन तेल की बिक्री कर रहे हैं जिससे बैंकों का और विशेषकर विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा तेल-तिलहन बाजार की कारोबारी धारणा प्रभावित हो रही है।

सूत्रों ने कहा कि हकीकत यह है कि मूंगफली तेल का थोक दाम काफी सस्ता है और इसके दाम एमएसपी से नीचे हैं। सूरजमुखी तेल से यह लगभग 10 रुपये किलो सस्ता बैठता है। इस नीचे दाम पर मांग उभरने से बीते सप्ताह मूंगफली तेल-तिलहन के दाम में भी मामूली सुधार देखा गया। उन्होंने कहा कि देश में बिनौला की आपूर्ति कुछ हजार गांठ की रह गई है जबकि इस मौसम में इसकी आपूर्ति लाखों गांठ की रहती है। मांग होने से बिनौला तेल में भी बीते सप्ताह सुधार आया। बिनौले की इस कमी को केवल पामोलीन ही पूरा करने की स्थिति में है। इस वजह से पाम-पामोलीन तेल की भी मांग है। इस वजह से बीते सप्ताह पाम-पामोलीन के दाम भी मजबूत बंद हुए।

सूत्रों ने कहा कि कई वर्षों के बाद किसानों को सोयाबीन और सरसों का जितना बेहतर दाम मिला है, उससे किसानों का उत्साह बढ़ेगा और इसका सीधा असर उत्पादन बढ़ने के रूप में देखने को मिल सकता है। इस उत्पादन वृद्धि के कारण ही आज देशी तेल के दाम सूरजमुखी के सामने नीचे हैं। उत्पादन बढ़ने के बाद खाद्य तेलों के दाम कम ही हुए हैं, किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, आयात कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और तेल-तिलहन उद्योग में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार में भी वृद्धि हो सकती है। ऐसी स्थिति रही तो आगे जाकर आयातित तेलों पर निर्भरता भी कम हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि बीते सप्ताह सरसों दाना 50 रुपये के सुधार के साथ 7,575-7,600 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों तेल 150 रुपये के सुधार के साथ 15,575 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल क्रमशः 25-25 रुपये के सुधार के साथ क्रमशः 2,575-2,675 रुपये और 2,575-2,720 रुपये टिन (15 किलो) पर मजबूत बंद हुआ।

समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज का थोक भाव क्रमशः 100-100 रुपये के सुधार के साथ क्रमशः 7,100-7,150 रुपये और 6,950-7,025 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

इसी प्रकार, दिल्ली में सोयाबीन तेल 25 रुपये के सुधार के साथ 15,475 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन इंदौर तेल 25 रुपये के सुधार के साथ 15,425 रुपये और सोयाबीन डीगम तेल 50 रुपये के सुधार के साथ 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। मांग रहने के बीच बीते सप्ताह मूंगफली तिलहन का दाम 50 रुपये के सुधार के साथ 6,675-7,250 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 25 रुपये के सुधार के साथ 15,575 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल पांच रुपये के सुधार के साथ 2,485-2,785 रुपये प्रति टिन पर बंद हुआ।

समीक्षाधीन सप्ताह में सीपीओ तेल का दाम 25 रुपये के सुधार के साथ 13,625 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। औद्योगिक मांग के बीच पामोलीन दिल्ली 50 रुपये के सुधार के साथ 15,600 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल 25 रुपये के सुधार के साथ 14,375 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

बाजार के तेजी के आम रुख के अनुरूप बिनौला तेल का दाम 50 रुपये के सुधार के साथ 15,650 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

भारत अंडर-19 महिला टीम ने श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप किया

चेन्नई, (वेब वार्ता)। भारतीय महिला अंडर-19 टीम ने श्रीलंका अंडर-19 टीम को तीसरे टी 20 में शनिवार को आठ गेंद शेष रहते सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया।

भारतीय टीम ने श्रीलंका को छह विकेट पर 116 रन पर रोकने के बाद 184 ओवर में तीन विकेट पर 120 रन बनाकर मुकाबला समाप्त कर दिया। कप्तान भाविका अहिरे ने पांच चौकों की मदद से 50 रन की मैच विजई पारी खेली। भाविका को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार श्रीलंकाई पारी में नाबाद 51 रन बनाने वाली नेतमी उपेक्षा को मिला।

नाओमी ओसाका ने फाइनल के एक सेट के बाद नाम वापस ले लिया

होम्बर्ग, (वेब वार्ता)। नाओमी ओसाका ने कैरोलिना मुचोवा के खिलाफ टेनिस में अपने पहले ग्रास कोर्ट फाइनल को जल्दी खत्म कर दिया, विंबलडन 2026 से एक हफ्ते पहले उन्हें एक छोटे मेडिकल टाइमआउट की जरूरत पड़ी। जर्मनी में बैड होम्बर्ग ओपन में महिला सिंगल्स के फाइनल में, मुचोवा ने पहला सेट 6-1 से जीता और ओसाका के नाम वापस लेने से पहले दूसरे सेट के पहले गेम में अपनी सर्व बनाए रखी।

जापानी स्टार पांच साल में अपने पहले टाइटल के लिए एक हफ्ते की शानदार मेहनत के बाद फाइनल में पहुंची थीं। उन्होंने इससे पहले चारों गेम में एक भी सेट नहीं गंवाया था। लेकिन फाइनल के पहले बीस मिनट के अंदर, उन्होंने लगातार तीन गेम गंवा दिए थे। एक ऐस ने आखिरकार मैच का उनका पहला और एकमात्र गेम पक्का कर दिया, जो फिर जल्दी ही उनसे दूर हो गया। ब्रेक के कारण ओसाका के फिजियो को उनके बंधे हुए बाएं टखने को देखने के लिए बुलाया गया, जो 29 जून को विंबलडन के पहले राउंड से पहले चिंता की बात थी।

मोहम्मद सालाह को घुटने में लगी चोट

न्यूयॉर्क, (वेब वार्ता)। मिस्र के स्ट्राइकर मोहम्मद सालाह को अगले शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम के वर्ल्ड कप के आखिरी-32 मुकाबले से पहले फिटनेस की दौड़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोच होसम हसन ने बताया कि सिएटल में ईरान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ मैच में उन्हें घुटने में चोट लगी है।

मैच के 57वें मिनट में सालाह की जगह मुस्तफा ज़िको ने ली और जब मैच के बाद उनके स्टार खिलाड़ी के बारे में पूछा गया, तो हसन ने बताया कि 34 साल के खिलाड़ी को अपने बाएं घुटने में दिक्कत महसूस हुई थी और मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही थी।

हसन ने प्रेस को बताया, "मैंने सालाह से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि वह ठीक हो जाएंगे और यह कोई गंभीर चोट नहीं है।" मिस्र के वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ग्रुप स्टेज से क्वालीफाई करने के बाद कोच ने दोहराया, "हमारे पास अभी भी मेडिकल टीम के साथ काम करने का समय है और मुझे लगता है कि वह वापस आ जाएगा। जब मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वह ठीक हो जाएगा।"

सलाह का अब तक टूर्नामेंट अच्छा रहा है, जिसमें एक गोल और दो असिस्ट शामिल हैं और उसकी लीडरशिप भी अफ्रीकी देश के लिए बहुत ज़रूरी है।

मेस्सी लगातार सात विश्व कप मैच में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने

अलिंग्टन, (वेब वार्ता)। लियोनेल मेस्सी लगातार सात विश्व कप मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

इस स्टार स्ट्राइकर ने जॉर्डन के खिलाफ शनिवार की रात यहां खेले गए अर्जेंटीना के ग्रुप चरण के अंतिम मैच में अपना 19वां गोल करके विश्व कप में सर्वाधिक गोल के अपने रिकार्ड को भी आगे बढ़ाया।

मेस्सी ने 80वें मिनट में पेनल्टी बॉक्स के ठीक बाहर फाउल होने के बाद फ्री किक पर गोल किया।

इससे पहले 39 वर्षीय मेस्सी फ्रांस के स्ट्राइकर जस्ट फॉन्टेन और ब्राजील के महान खिलाड़ी जैरज़िन्हो के साथ विश्व कप के लगातार छह मैचों में गोल करने वाले केवल तीन खिलाड़ियों में से एक थे।

फीफा विश्वकप पुर्तगाल के खिलाफ कोलंबिया का गोल रहित ड्रा

➲ नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।

मियामी, (वेब वार्ता)। कोलंबिया ने पुर्तगाल के खिलाफ कड़े मुकाबले में गोल रहित ड्रॉ खेलकर फीफा विश्वकप के ग्रुप के में शीर्ष स्थान हासिल किया। मैच के आखिरी पलों में वीएआर के दखल की वजह से उन्हें जीत दिलाने वाला गोल नहीं मिल पाया।

यहां हार्ड रॉक स्टेडियम में रविवार को हुए मुकाबले में मिले गोल रहित नतीजे के बाद कोलंबिया तीन मैचों में सात अंकों के साथ ग्रुप विनर के तौर पर राउंड ऑफ 32 में पहुंचा, जबकि पुर्तगाल भी पांच अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।

मैच में कोलंबिया ने बेहतर मौके बनाए, जबकि पुर्तगाल ने भी तेज जवाबी हमला से खतरा पैदा किया, लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। सबसे अहम पल स्टॉपेज टाइम के आखिर में आया जब डिफेंडर डेविंसन सांचेज ने एक चालाकी से लिए गए कॉर्नर पर सबसे ऊंची छलांग लगाकर हेडर से गोल किया, जिससे कोलंबियाई समर्थकों में जबरदस्त जश्न का माहौल बन गया। हालांकि, लंबे रिव्यू के बाद गोल को रद्द कर दिया गया क्योंकि रिप्ले में सांचेज का दाहिना पैर थोड़ा सा ऑफ़साइड दिखा, जिससे कोलंबिया को एक अंक से ही संतोष करना पड़ा।

अनुभवी प्लेमेकर जेम्स रोड्रिगेज ने एक बार फिर शानदार खेल दिखाया। दूसरे हाफ में वे कोलंबिया के लिए गोल करने के सबसे करीब पहुंचे, जब उनकी एक 'डिपिंग वॉली' हल्की सी दिशा बदलने के बाद क्रॉसबार के ठीक ऊपर से निकल गई।

वहीं, पुर्तगाल ने कुछ समय तक बॉल पर कब्ज़ा बनाए रखा, लेकिन वे इसे साफ़-सुथरे मौकों में बदलने में संघर्ष करते दिखे। ब्रूनो फर्नांडीस ने दूर से शॉट मारा जो बाहर चला गया, जबकि नूनो मेंडेस और जोआओ फेलिक्स कोलंबिया के अनुशासित रक्षापंक्ति को भेदने में नाकाम रहे। इसके बाद दोनों टीमों ने जीत की तलाश में आखिरी समय में सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी उतारे।

गोलकीपर डियोगो कोस्टा ने डेनियल मुनोज़ को गोल करने से रोकने के लिए आखिरी समय में अहम बचाव किया। वहीं, कोलंबिया ने पेनल्टी के लिए भी अपील की, लेकिन वह सफल नहीं रही; यह अपील तब की गई थी जब नूनो मेंडेस के दबाव में लुइस सुआरेज़ बॉक्स के अंदर गिर गए थे। 25 फीफा वर्ल्ड कप मैचों में पहली बार गोल न कर पाने के बावजूद, कोलंबिया के मजबूत डिफेंस ने यह सुनिश्चित किया कि वे ग्रुप स्टेज में बिना कोई मैच हारे आगे बढ़ें। यह ड्रॉ उन्हें पहला स्थान दिलाने के लिए काफ़ी था। कोलंबिया अब राउंड ऑफ 32 में घाना का सामना करेगा, जबकि पुर्तगाल नॉकआउट स्टेज में क्रोएशिया से भिड़ेगा।

उज्बेकिस्तान को हराकर डी आर कांगो नॉकआउट में पहुंचा

अटलांटा, (वेब वार्ता)। डीआर कांगो ने फीफा विश्वकप 20226 के ग्रुप के मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ ही कांगो ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की की।

रविवार को मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में हाफटाइम में एल्डोर शोमुरोदोव के शानदार शुरुआती गोल से पिछड़ने के बाद, अफ्रीकी टीम ने ब्रेक के बाद दृढ़ संकल्प और आक्रामक इरादे के साथ वापसी की। योआने विसा ने दो गोल किए, जिसमें स्टॉपेज-टाइम में किया गया एक शानदार गोल भी शामिल था, जबकि फिस्टन मायेले ने निर्णायक गोल करके यादगार वापसी पूरी की। इस जीत ने डीआर कांगो को नॉकआउट चरण में पहुंचा दिया, जहां उनका मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जबकि उज़्बेकिस्तान लगातार तीसरी हार के बाद बिना किसी अंक के टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

उज्बेकिस्तान ने धमाकेदार शुरुआत की और लगभग पहले ही मिनट में गोल कर दिया था, जब शोमुरोदोव ने करीब से शॉट मारा, लेकिन ऑफसाइड होने के कारण गोल को अमान्य करार दिया गया। स्ट्राइकर को ज्यादा देर तक गोल करने से नहीं रोका जा सका। 10वें मिनट में, डिफेंस में हुई गलतफहमी का फायदा उठाते हुए शोमुरोदोव ने गेंद पर कब्जा किया और आगे बढ़ रहे गोलकीपर के ऊपर से गेंद को चिप करके उज़्बेकिस्तान को 1-0 की बढ़त दिलाई।

डीआर कांगो धीरे-धीरे खेल में लौटा और उन्हें लगा कि हाफटाइम से पहले नथानिएल म्बुकु ने बराबरी का गोल कर दिया है। हालांकि, लंबे वीएआर रिव्यू के बाद गोल को अमान्य कर दिया गया रेफरी ने फैसला सुनाया कि म्बुकु ने गोल से पहले के मूव में रुस्तम नसरुल्लाव के खिलाफ फाउल किया था। ज्यादा समय तक गेंद अपने पास रखने के बावजूद, कांगो की टीम शुरुआती दौर में उज़्बेकिस्तान के अनुशासित डिफेंस को तोड़ने में संघर्ष करती रही और हाफटाइम तक एक गोल से पीछे रही।

दुबारा खेल फिर से शुरू होने के बाद मैच का रुख पूरी तरह बदल गया क्योंकि कांगो ने गति बढ़ाई और बार-बार उज़्बेकिस्तान के पेनल्टी एरिया में खतरा पैदा किया। उनकी मेहनत 66वें मिनट में रंग लाई जब विसा एक क्रॉस पर तेजी से आगे बढ़े और बॉक्स के अंदर अब्दुकोदिर खुसानोव के गलत समय पर किए गए चैलेंज के कारण गिर गए। रेफरी ने तुरंत पेनल्टी स्पॉट की ओर इशारा किया, और विसा ने शांति से गोलकीपर उत्किर नेमातोव को गलत दिशा में छकाते हुए 68वें मिनट में स्कोर बराबर कर दिया। बराबरी के गोल ने मैच का रुख पूरी तरह से अफ्रीकी टीम के पक्ष में मोड़ दिया। मैनेजर के किए गए बदलाव भी निर्णायक साबित हुए। दूसरे हाफ के बीच में मैदान पर आए मेशैक एलिया ने अटैक में नई तेजी लाई और जीत दिलाने वाले गोल में अहम भूमिका निभाई।

78वें मिनट में, एलिया पेनल्टी एरिया में तेजी से घुसे और उनका शॉट डिफ्लेक्ट होकर मायले के पास पहुंचा। मायले ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उस ढीली गेंद को करीब से नेट में पहुंचाया और कांगो को 2-1 की बढ़त दिला दी। उज्बेकिस्तान वापसी करने के लिए संघर्ष करता रहा और खेल के आखिरी पलों में ज़्यादा मौके नहीं बना पाया, जबकि DR कांगो ने बॉल पर कब्जी बनाए रखा और खेल पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। स्टॉपेज टाइम के पहले मिनट में उनकी श्रेष्ठता साबित हो गई, जब एलिया ने फिर से अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गेंद को अपने पास बनाए रखा और फिर एरिया के बाहर विसा को पास दिया। न्यूकैसल यूनाइटेड के इस फॉरवर्ड ने गेंद को अपने दाहिने पैर पर लिया और लगभग 20 गज की दूरी से एक शानदार लो शॉट मारकर निचले कोने में गोल किया। इस तरह उन्होंने शानदार अंदाज़ में जीत पक्की की और टूर्नामेंट में अपना तीसरा गोल दागा।

अब आयरलैंड की महिलाओं का कमाल, वेस्ट इंडीज को हराया

➲ ब्रिस्टल, (वेब वार्ता)।

आयरलैंड की पुरुष टीम की विश्व चैम्पियन भारत पर जीत के बाद अब आयरलैंड की महिला टीम ने ओर्ला प्रेंडरगैस्ट ने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन की बदौलत शनिवार को वेस्ट इंडीज को छह विकेट से हराकर महिला टी 20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की।

वेस्टइंडीज को 29 रन देकर 1 विकेट लेकर 7 विकेट पर 128 रन पर रोकने में मदद करने के बाद, प्रेंडरगैस्ट ने 44 गेंदों पर 63 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली, जिससे आयरलैंड ने 11 गेंद बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया। इस नतीजे ने न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल की उम्मीदों को भी जिंदा रखा और अगर वे अपने आखिरी ग्रुप गेम में इंग्लैंड को हरा देते हैं तो वे आगे बढ़ जाएंगे। इस बीच, वेस्टइंडीज के चांस सीधे इंग्लैंड की जीत से जुड़े हैं।

पहले बैटिंग करने के लिए कहने पर, वेस्टइंडीज धीमी, दो-तरफ़ा पिच पर कभी भी आसानी से रन नहीं बना पाया। उन्होंने शेमेन कैम्पबेल को जल्दी खो दिया, जिसके बाद हेली मैथ्यूज (22), स्टेफनी टेलर (16) और डिएंड्रा डॉटिन (21) सभी ने शुरुआत की लेकिन जल्दी रन बनाने के लिए संघर्ष किया। आयरलैंड के बॉलर्स ने अपनी पेस को होशियारी से मिलाया और डिसिप्लिन्ड लाइन से बैट्समैन पर दबाव बनाया, जबकि स्पिनर खास तौर पर असरदार थे।

चिनेल हेनरी के 21 गेंदों पर नाबाद 27 रन ने वेस्टइंडीज को आखिर में बढ़त दिलाई, लेकिन आखिरी आठ ओवर में चार विकेट गंवाने के बाद भी वे 7 विकेट पर 128 रन ही बना पाए।

पांचवें ओवर में कप्तान गैबी लुईस के आउट होने के बावजूद आयरलैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की। प्रेंडरगैस्ट और एमी हंटर ने दूसरे विकेट के लिए 62 रन की तेज़ साझेदारी करके पारी को संभाला और ज़रूरी रन रेट को कंट्रोल में रखा। हंटर ने एफी फ्लेचर का शिकार होने से पहले 28 रन बनाए, लेकिन प्रेंडरगैस्ट ने बीच के ओवरों में अपनी रफ़्तार बदली, और शानदार अर्धशतक बनाने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीप और पुल किया।

वेस्ट इंडीज ने थोड़ी उम्मीद जगाई जब हेली मैथ्यूज ने प्रेंडरगैस्ट को 63 रन पर आउट किया, जब अभी भी 21 रन चाहिए थे, लेकिन रेबेका स्टोकेल शांत रहीं और नाबाद 16 रन बनाए और लुईस लिटिल ने विजई बाउंड्री लगाई, जिससे आयरलैंड ने 18.1 ओवर में लक्ष्य का पीछा पूरा कर लिया।

क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया, पुर्तगाल के साथ नॉकआउट का मुकाबला तय किया

➲ फिलाडेल्फिया, (वेब वार्ता)।

क्रोएशिया ने अपने आखिरी ग्रुप एल मैच में घाना पर 2-1 से शानदार जीत हासिल करके फीफा विश्वकप के 'राउंड ऑफ 32' में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ उसने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया।

लिंकन फाइनेंशियल फील्ड में रविवार को खेले गये मुकाबले में मिली इस जीत के साथ क्रोएशिया के तीन मैचों में सात अंक हो गए, जो इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर रहने के लिए काफी थे। इंग्लैंड ने ग्रुप एल के दूसरे मैच में पनामा को 2-0 से हराया था। घाना ने एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ चार अंकों पर अपना अभियान खत्म किया।

मैच के शुरुआती आधे हिस्से में क्रोएशिया का दबदबा रहा। उन्होंने गेंद पर कब्जा बनाए रखा और घाना की रक्षापंक्ति पर हमले करते रहे, हालांकि शुरुआत में गोल करने के बहुत कम साफ मौके बने। हाफ के बीच में निकोला व्लासिक गोल करने के सबसे करीब पहुंचे, जब उनका शॉट पोस्ट से टकराया, जो क्रोएशिया के बढ़ते दबदबे का संकेत था।

31वें मिनट में पेटार सुसिक ने टीम को बढ़त दिलाई। माटेओ कोवासिच ने मिडफील्डर की ओर एक सटीक पास बढ़ाया और सुसिक ने शांति से डिफेंडरों की भीड़ के बीच से नीचे-बाएं कोने में शॉट मारा, जिससे घाना के गोलकीपर बेंजामिन असारे के पास बचाव का कोई मौका नहीं बचा। हाफ-टाइम से पहले घाना को अच्छे मौके बनाने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हाफ-टाइम के बाद वे नए इरादे के साथ मैदान पर उतरे। ओटो एडो की टीम ने धीरे-धीरे क्रोएशिया पर दबाव बनाया और सेट-पीस से खतरा पैदा करना शुरू किया, जिससे यूरोपीय टीम को लंबे समय तक रक्षात्मक खेल खेलना पड़ा। उनकी मेहनत 73वें मिनट में रंग लाई, जब सबस्टिट्यूट अर्नेस्ट नुअमाह ने पेनल्टी एरिया में एक बेहतरीन फ्री-किक दी और डेरिक लुकासेन ने साइड-फुट से गेंद को नेट में पहुंचा दिया। असिस्टेंट रेफरी ने शुरू में ऑफसाइड का इशारा किया, लेकिन लगभग चार मिनट तक चले वीएआर रिव्यू के बाद गोल को मान्यता दे दी गई, जिससे घाना के खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई।

बराबरी के गोल ने क्रोएशिया को कुछ ही देर के लिए परेशान किया। 10 मिनट बाद, ज़्लात्को डालिच की टीम ने सेट-पीस से फिर से बढ़त बना ली। मारियो पासालिच के शॉट को असारे ने शानदार ढंग से बचाया, जिससे कॉर्नर मिला, और लुका मोड्रिच ने बॉक्स में बेहतरीन डिलीवरी दी। व्लासिक ने अपनी दौड़ का सही समय चुना और नीचे-बाएं कोने में ज़ोरदार हेडर लगाया; गेंद पोस्ट के अंदरूनी हिस्से को छूते हुए लाइन पार कर गई। इस असिस्ट ने मोड्रिक के शानदार करियर में एक और उपलब्धि जोड़ दी; 40 साल की उम्र में वे 1966 से अब तक के ऑप्टा रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड कप में असिस्ट करने वाले सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी बन गए।

घाना ने सात मिनट के अतिरिक्त समय में एक आखिरी कोशिश की, लेकिन क्रोएशिया ने मजबूती से बचाव किया। कमालदीन सुलेमाना की जगह आए नुअमाह ने क्रोएशियाई डिफेंस को परेशान करना जारी रखा, जबकि एंटोनी सेमेन्यो ज़ोरदार टक्कर के बाद इलाज कराकर खेलते रहे। हालांकि, 'ब्लैक स्टार्स' कोई और साफ़ मौका नहीं बना पाए और क्रोएशिया ने आखिरी सीटी बजने तक अपनी मामूली बढ़त को सफलतापूर्वक बनाए रखा।

इस नतीजे के साथ क्रोएशिया नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया है, जहां राउंड ऑफ 32 में उनका सामना पुर्तगाल से होगा। घाना के लिए, दूसरे हाफ में बेहतर खेल के बावजूद इस हार के साथ उनका वर्ल्ड कप का सफ़र खत्म हो गया। 'ब्लैक स्टार्स' चार अंकों के साथ बाहर हुए, और उनके बाहर होने से टूर्नामेंट से स्कॉटलैंड के बाहर होने की भी पुष्टि हो गई।

धरती आबा और जनमन योजना
जनजातीय क्षेत्रों के लिए वरदान : राज्यपाल

➲ भोपाल, (वेब वार्ता)।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि ₹धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना₹ और ₹प्रधानमंत्री जनमन योजना₹ जनजातीय क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। जनजातीय क्षेत्र के ग्रामों बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंa ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक सिकलसेल बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए मरीजों के उपचार के साथ-साथ जन-जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है।

राज्यपाल श्री पटेल रविवार ने यह बात खरगोन के झिरन्या में आयोजित सिकलसेल शिविर कार्यक्रम में कहीं। इस दौरान ब्लड बैंक का शुभारंभ किया तथा दो एंबुलेंस और एक शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पल्स पोलियो अभियान के तहत कुमारी आस्था को पोलियोरोधी दवाई पिलाई। उन्होंने सिकलसेल प्रमाण पत्र प्रदान किये। उन्होंने क्षय रोगियों को फूड बास्केट भेंट की। राज्यपाल श्री पटेल ने इस अवसर पर ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी के ₹मन की बात₹ कार्यक्रम को भी सुना।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि सिकलसेल रोग अनुवांशिक रोग है। इसकी जांच गर्भावस्था में भी संभव है। बच्चों के गर्भावस्था के दौरान भी सिकल सेल रोग का उपचार प्रारंभ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ₹सिकलसेल मित्र₹ मरीजों की मदद में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलोपैथिक पद्धति के साथ-साथ आयुर्वेद में भी सिकलसेल रोग का बेहतर उपचार उपलब्ध है। अब टीबी रोग का बेहतर उपचार उपलब्ध है। मरीज यदि 6 माह तक नियमित रूप से दवाई ले, तो टीबी रोग ठीक किया जा सकता है।

राज्यपाल श्री पटेल ने इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा विकास योजनाओं के प्रदर्शन के लिए लगाए गए स्टाल पर जाकर उपस्थित अधिकारियों से विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली।

सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी मे विकास और गरीबों के कल्याण के काम तेजी से हो रहे हैं। झिरन्या में 1500 करोड़ रुपए लागत की उदवहन सिंचाई योजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र के किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी।

राज्यपाल श्री पटेल ने मारूगढ़ निवासी कालू के पीएम आवास में किया भोजन

राज्यपाल श्री पटेल ने रविवार को खरगोन जिले के झिरन्या विकासखंड की ग्राम पंचायत शाहपुर के ग्राम मारूगढ़ निवासी कालू पिता रतन के प्रधानमंत्री आवास में भोजन किया। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में विधायक श्रीमती छाया मोरे, खरगोन के विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार, महेश्वर के विधायक श्री राजकुमार मेव, जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती नंदा ब्राह्मणे एवं कलेक्टर श्रीमती भव्या मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक श्री रवींद्र वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।

जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन दिवस पर होंगी विशेष ग्राम सभाएँ

» मुख्यमंत्री के संदेश का किया जायेगा वाचन

» अभियान अंतर्गत हुए कार्यों का होगा प्रस्तुतिकरण

भोपाल, (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर 19 मार्च से प्रारंभ हुए जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन 30 जून 2026 को होगा। अभियान के दौरान लगभग 3.62 लाख से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है, जिनमें ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा, औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन, जल गुणवता परीक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नदी पुनर्जीवन तथा जन-जागरुकता से संबंधित विविध गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान 2026₹ का समापन जिले के प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति में समारोह पूर्वक किया जा रहा है।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जायेगा सम्मानित

अभियान के समापन के अवसर पर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संदेश का वाचन किया जाएगा और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत निष्पादित कार्यों, उपलब्धियों तथा लाभान्वित परिवारों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। जन-सहभागिता, श्रमदान एवं नवाचार के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों, जलदूतों एवं सामुदायिक संगठनों का सम्मान किया जाएगा। जल संरक्षण, जल सुरक्षा, भू-जल संवर्धन तथा वर्षा जल संचयन की भावी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी तथा ग्राम स्तर पर आगामी वर्ष के लिये कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

आगामी 01 जुलाई 2026 से प्रारंभ होने वाली ₹विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VBG RAM G)₹ के विभिन्न आयामों एवं संभावित लाभों के संबंध में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही अभियान के अंतर्गत निर्मित अथवा पूर्ण हुई महत्वपूर्ण जल संरचनाओं का जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकार्पण कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स गणराज्य द्वारा सम्मानित करने पर दी बधाई

भोपाल, (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सेशल्स गणराज्य द्वारा विशेष सम्मान ₹गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज़न₹ से सम्मानित किये जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए मध्यप्रदेश के समस्त नागरिकों की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई दी है।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को सेशल्स गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवमयी क्षण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को इसके पूर्व अनेक राष्ट्र सम्मानित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सेशल्स गणराज्य द्वारा प्रदत्त सम्मान पर्यावरण संरक्षण सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी और वैश्विक सहयोग के प्रति प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है।

सीधी संभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता श्री रंजीत साहू निलंबित

भोपाल, (वेब वार्ता)। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने हनुमना स्थित 02 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उपकरणों एवं विभिन्न विद्युत कंपनियों की सामग्री के संभावित दुरुपयोग संबंधी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्यालय कार्यपालन अभियंता(एस.टी.एम.-एस.टी.सी.), संभाग सीधी में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता श्री रंजीत कुमार साहू को निलंबित कर दिया है।

प्राप्त शिकायत के आधार पर मुख्य अभियंता (प्रवर्तन) रीवा द्वारा गठित जांच समिति ने स्थल निरीक्षण, अभिलेखों के परीक्षण तथा संबंधित अधिकारियों के कथनों के आधार पर विस्तृत जांच की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित 02 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के विद्युत संयोजन एवं लाइन विस्तार का कार्य मै. ओम एंटरप्राइजेज, जिसकी प्रोपराइटर श्रीमती ममता कुमारी पत्नी श्री रंजीत कुमार साहू हैं, द्वारा किया गया था। जांच के दौरान स्थापित उपकरणों एवं सामग्री के परीक्षण में कुछ विद्युत उपकरणों पर म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का नाम अंकित पाया गया, जबकि कंट्रोल केबल पर मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का उल्लेख पाया गया। इसके अतिरिक्त वीसीबी की नेम प्लेट पर क्रेता संबंधी विवरण मिटा हुआ पाया गया, जिसके संबंध में संबंधित कंपनियों से अभिलेखीय सत्यापन की अनुशंसा की गई है।

जांच समिति ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया श्री रंजीत कुमार साहू की संभावित संलिप्तता का उल्लेख किया, जिसके आधार पर कंपनी प्रबंधन ने उनके विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता (संचालन/संधारण) वृत्त, उमरिया निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि कंपनी की सामग्री, संसाधनों एवं परिसंपत्तियों के संभावित दुरुपयोग अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता के मामलों में शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई गई है। जांच में सामने आए सभी तथ्यों का संबंधित कंपनियों से अभिलेखीय सत्यापन कराया जा रहा है तथा अंतिम निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. पी.वी. नरसिम्हा राव जयंती पर किया नमन

भोपाल, (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. पी.वी. नरसिम्हा राव की जयंती पर स्मरण कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के विकास में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा।

इंदौर के डायल-112 हीरोज, रास्ता भटके 10 वर्षीय बालक को सुरक्षित दादा के सुपुर्द किया

भोपाल, (वेब वार्ता)। इंदौर जिले के थाना खजराना क्षेत्र में डायल-112 जवानों की संवेदनशील एवं तत्पर कार्रवाई से घर से निकलकर रास्ता भटक गए 10 वर्षीय बालक को सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुँचाया गया। समय पर की गई इस मानवीय पहल से बालक को सुरक्षा एवं परिवार का सान्निध्य पुनः प्राप्त हो सका।

27 जून को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खजराना क्षेत्र अंतर्गत सेरेटन होटल के सामने एक 10 वर्षीय बालक अकेला मिला है। पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही खजराना थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112 वाहन को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

डायल-112 स्टाफ प्रधान आरक्षक श्री महेंद्र सिंह तोमर, आरक्षक श्री महेश कुशवाह एवं पायलट श्री अंकित बंसल ने मौके पर पहुँचकर बालक को सुरक्षित संरक्षण में लिया। इसके पश्चात डायल-112 टीम ने तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ आसपास क्षेत्र में पूछताछ कर उसके परिजनों की तलाश प्रारंभ की। पूछताछ के दौरान बालक के दादा का पता चला। बालक द्वारा पहचान एवं आवश्यक सत्यापन उपरांत उसे सुरक्षित उसके दादा के सुपुर्द किया गया।डायल-112 जवानों की संवेदनशील एवं समर्पित कार्यवाही से एक मासूम बालक को सुरक्षित उसके परिवार तक पहुँचाया जा सका।

प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कुकरू पर्यटन का बनेगा प्रमुख केंद्र : मुख्यमंत्री

➲ भोपाल, (वेब वार्ता)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को प्रदेश के बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि कुकरू में पर्यटन विकास के लिए 15 करोड़ रुपये की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को बैतूल के पर्यटन स्थल कुकरू के भ्रमण के दौरान यह बात कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को बैतूल जिले के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकुरू के रेस्ट हाउस परिसर में योगाभ्यास कर दिन की शुरूआत की। उन्होंने योग कर प्रदेशवासियों को अपनी दैनिक जीवनशैली में योग को शामिल करने का संदेश दिया। प्राकृतिक वादियों के बीच आयोजित योग सत्र में मुख्यमंत्री ने योग साधक की भांति विभिन्न योगासन कर सभी को नियमित योग के प्रति प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने योगाभ्यास के दौरान मयूरासन, शीर्षासन सहित अन्य आसनों का भी सहजता एवं पारंगत रूप से प्रदर्शन किया। उन्होंने ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वक्रासन, भुजंगासन एवं शलभासन सहित अनेक योगासनों का स्थानीय ग्रामीणों के साथ सामूहिक अभ्यास किया। साथ ही नाड़ी शोधन, तितली एवं भ्रामरी प्राणायाम भी किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुकरू से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। साथ ही कुकरू में पर्यटन विकास की कार्ययोजना का प्रेजेंटेशन भी देखा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कुकरू में ईको टूरिज्म, सनराइज एवं सनसेट प्वाइंट सहित अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थलों का विकास किया जाएगा।

पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त ईको रिसोर्ट एवं अन्य पर्यटन अधोसंरचना विकसित की जाएगी। साथ ही ट्रैकिंग सहित विभिन्न एडवेंचर स्पोर्ट्स और रोमांचक गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कुकरू के पर्यटन विकास के लिए बजट में और वृद्धि भी की जाएगी।

जनजातीय समूहों के लिए बनेंगे होमस्टे, एमपी टूरिज्म करेगा बुकिंग

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्थानीय जनजातीय ग्रामीण समूहों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के लिए कुकरू में होमस्टे विकसित किए जाएंगे। इन होमस्टे का संचालन मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम (एमपीटी) के होटलों की तर्ज पर व्यवस्थित रूप से किया जाएगा तथा इनकी बुकिंग की व्यवस्था मध्यप्रदेश टूरिज्म द्वारा की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कुकरू अपनी उत्कृष्ट कॉफी के साथ-साथ कोदो कुटकी, आंवला, हनी, हर्रा, बहेड़ा, सफेद मूसली, भिलवा एवं अन्य प्राकृतिक उत्पादों के लिए भी प्रसिद्ध है।

झाबुआ से देश को पोलियो मुक्त रखने का संकल्प
मंत्री सुश्री भूरिया ने किया राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ

➲ भोपाल, (वेब वार्ता)।

देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के राष्ट्रीय संकल्प के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने रविवार को झाबुआ जिले में तीन दिवसीय 'राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान' का शुभारंभ किया। जिला चिकित्सालय झाबुआ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री सुश्री भूरिया ने फीता काटकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान के जिला स्तरीय चरण की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं बच्चों को पोलियो रोधक दवा की दो बूंद पिलाकर आम जनता को जागरूकता का संदेश दिया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने पोलियो उन्मूलन की दिशा में भारत की ऐतिहासिक सफलता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पोलियो उन्मूलन की दिशा में हमारे देश ने दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है, लेकिन इस बड़ी सफलता और सुरक्षा चक्र को बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हर पीढ़ी के प्रत्येक बच्चे को समय पर पोलियो रोधक दवा की खुराक मिले। मंत्री सुश्री भूरिया ने बल देकर कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य और उनका सुरक्षित भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने सभी नागरिकों और अभिभावकों से भावुक अपील की कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो बूथ पर ले जाकर दवा अवश्य पिलवाएं और इस जनहितकारी अभियान को सफल बनाने में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएं।

मंत्री सुश्री भूरिया द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत झाबुआ जिले में 0 से 5 वर्ष तक के कुल 2,13,504 बच्चों को दवा पिलाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) एम.एल. चोपड़ा ने बताया कि जमीनी स्तर पर एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसके तहत जिले में कुल 1,185 टीमें मुस्तैद की गई हैं।

पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, जेल एवं फॉरेंसिक के अधिकारी एक मंच पर

➲ भोपाल, (वेब वार्ता)।

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा "ICJS Implementation and Digital Integration" विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का भव्य एवं सफल आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार (मिंटो हॉल), भोपाल में किया गया। यह कार्यशाला अपने स्वरूप और उद्देश्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय आयोजन साबित हुई, जिसमें Interoperable Criminal Justice System (ICJS) के अंतर्गत समस्त स्तंभ – पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य –एक ही मंच पर एकत्रित हुए। कार्यशाला में इन विभिन्न स्तंभो के प्रतिनिधियों ने आपसी अनुभवों, व्यावहारिक चुनौतियों तथा समाधान-आधारित विचारों को साझा करते हुए ICJS के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया।

उक्त कार्यशाला का आयोजन माननीय न्यायमूर्ति संजीव एस. कालगांवकर , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य आतिथ्य एवं पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, SCRB जयदीप प्रसाद के नेतृत्व तथा पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायणचारी मिश्र के समन्वय में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति संजीव एस. कालगांवकर, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, म.प्र., पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा एवं मंचासीन अतिथि गणों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य ICJS के अंतर्गत पुलिस, अभियोजन, न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक व स्वास्थ्य विभागों के मध्य डिजिटल समन्वय को सशक्त बनाना तथा क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों और कमियों पर संवाद कर उनके समाधान की रूपरेखा तैयार करना था।

कार्यशाला में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, अभियोजन, जेल, फॉरेंसिक और स्वास्थ्य विभागों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

स्वागत उद्बोधन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, SCRB श्री जयदीप प्रसाद ने कहा कि ICJS केवल एक सॉफ्टवेयर परियोजना नहीं, बल्कि देश की संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को डिजिटल रूप से जोड़ने वाला राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने कहा कि पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभागों के बीच निर्बाध डिजिटल समन्वय स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्यों, राज्य की वर्तमान प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी

मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव एस. कालगांवकर ने कहा कि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) केवल एक तकनीकी मंच नहीं, बल्कि पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, फॉरेंसिक एवं अन्य विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने वाला एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में तकनीक को विधिक मान्यता दी गई है और भविष्य की न्याय व्यवस्था डिजिटल साक्ष्यों, रियल-टाइम सूचना आदान-प्रदान तथा तकनीक आधारित प्रक्रियाओं पर आधारित होगी। मध्यप्रदेश द्वारा ई-समन, ई-वारंट, CCTNS आधारित समन्वय एवं डिजिटल संचार जैसी पहलों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था की सफलता का वास्तविक पैमाना आम नागरिक को मिलने वाला लाभ है। उन्होंने डिजिटल साक्ष्यों के सुरक्षित प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण डेटा, तकनीकी नवाचारों के उपयोग तथा सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। उन्होंने कहा कि CCTNS 2.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, त्वरित एवं स्मार्ट बनाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक का दुरुपयोग करने वाले अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी आधुनिक तकनीकों को तेजी से अपनाना होगा। उन्होंने ई-कोर्ट, ई-पेमेंट, भूमि अभिलेखों के एकीकरण तथा ऑनलाइन न्यायिक सेवाओं जैसी डिजिटल पहलों की सराहना करते हुए डिजिटल चार्जशीट, सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज, दस्तावेजों की सुव्यवस्थित इंडेक्सिंग एवं विभिन्न एजेंसियों के बीच निर्बाध डेटा साझा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक इरशान सईद द्वारा ए -352, न्यू अशोक नगर, दिल्ली 110096 से प्रकाशित एवं साईं प्रिंटिंग प्रेस, डी 85, सेक्टर 6, नोएडा-201301 उत्तर प्रदेश से मुद्रित। संपादक सईद अहमद
RNI No.DELHIN/2014/56101 संपर्क सूत्र : +91-8587018587 , Email : webvarta@gmail.com, समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।